लखनऊ
शनिवार 17 जनवरी, 2026
वर्ष : 11 | अंक: 148
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8
UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक
आर्यावर्त क्रांति

आत्मीयता को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ग़लतियों को हम उदारतापूर्वक क्षमा करना सीखें।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi
NIGHT 10° Low

संक्षेप

सत्य की हुई जीत, Bengal सरकार पर बरसे तरुण चुघ, बोले- ममता बनर्जी को SC की फटकार

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। चुघ ने न्यायालय की इस कार्रवाई को 'सत्य की जीत' और ममता बनर्जी की क्रूर, भ्रष्ट सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बताया, जो माफियाओं को संरक्षण देती है। एएनआई से बात करते हुए चुघ ने कहा, 'ईडी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की फटकार सत्य की जीत है और ममता बनर्जी की क्रूर, भ्रष्ट सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है, जो माफियाओं को संरक्षण देती है। ममता सरकार संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में खुलेआम हस्तक्षेप कर रही है, कानून-व्यवस्था को कगार पर धकेल रही है और केवल अराजकता फैला रही है... ममता बनर्जी कितना भी दबाव डालें, लूट और भ्रष्टाचार की जांच नहीं रुकेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुघ की ये टिप्पणी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करने के बाद आई है। ईडी ने याचिका में आरोप लगाया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के परिसर में तलाशी अभियान के दौरान राज्य के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था।

संजय कपूर की करोड़ों की संपत्ति पर अधिकार की लड़ाई, प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से मांगे गोपनीय रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रिया कपूर ने यह दावा करते हुए कि वह दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और प्रत्यक्ष कानूनी उत्तराधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संजय कपूर और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के तलाक की कार्यवाही से संबंधित 2016 की हस्तांतरण याचिका के संपूर्ण अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित उत्तराधिकार मामलों में इन गोपनीय अदालती अभिलेखों तक पहुंच की उन्हें वास्तविक रूप से आवश्यकता है और मृतक की संपत्ति से संबंधित उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। आवेदन के अनुसार, संजय कपूर ने मुंबई के पारिवारिक न्यायालय से दिल्ली में तलाक का मामला स्थानांतरित करने के लिए 2016 में स्थानांतरण याचिका दायर की थी। इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, संजय कपूर और करिश्मा कपूर ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों को सुलझा लिया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल, 2016 को दोनों पक्षों के बीच सहमति की विस्तृत शर्तों को दर्ज करने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। प्रिया कपूर ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि संजय कपूर का 12 जून,

पीएम मोदी ने की राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत, कहा- भारतीयों द्वारा भारतीय सर्वरों पर तैयार हो स्वदेशी एआई

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भविष्य में किसी देश को आगे रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्रांति जरूरी होगी और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वदेशी एआई भारतीयों द्वारा भारतीय सर्वरों पर ही तैयार हो।

पीएम मोदी ने यहां भारत मंडपम् में स्टार्टअप इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 10 साल में देश में एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है। सरकार ने विश्वास और पारदर्शिता का माहौल बनाया है। जन विश्वास कानून बनाया है। स्टार्टअप के लिए कई कानूनों में स्व-प्रमाणन की सुविधा दी गयी है ताकि स्टार्टअप का समय मुकदमेबाजी में बर्बाद न हो।

इससे पहले पीएम मोदी ने कुछ स्टार्टअप कंपनियों के स्टॉल पर जाकर उनके द्वारा किये जा रहे काम के बारे में जाना। इसके बाद कुछ स्टार्टअप ने मंच से अपनी यात्रा और स्टार्टअप इंडिया मिशन से मिले लाभ के बारे में बताया। मोदी ने कहा कि आज का अनुसंधान ही कल की बौद्धिक संपदा बनती है। जो देश एआई की क्रांति में जितना आगे होगा वह उतनी ही लाभ की स्थिति में होगा।

कार्यक्रम में मौजूद स्टार्टअप का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'यह काम आपको करना होगा। इंडिया एआई मिशन के जरिये 38 हजार से अधिक जीपीयू को ऑनबोर्ड किया है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्वदेशी एआई भारतीयों द्वारा भारतीय सर्वरों पर ही तैयार हों।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का नौजवान आज खिंची-खिंचाई लकीर पर आराम से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए नये रास्ते खुद बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि जोखिम लेने वालों को अब सम्मान मिलता है और यह अब फैशन बन रहा है।

इसी संदर्भ में अपनी सरकार की काम करने की शैली का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ₹जोखिम लेना मेरी भी आदत रही है। जिन कामों को दशकों से किसी ने नहीं छुआ, जिनके लिए लोग कहते थे कि राजनीतिक जोखिम है, मैं उन्हें अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो देश के करोड़ों परिवारों का होगा।'

मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन ने देश में एक नयी संस्कृति को जन्म दिया है। पहले नया कारोबार केवल बड़े-बड़े घरों के बच्चे ही लेकर आते थे क्योंकि उन्हें ही आराम से फंडिंग मिलती थी। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे सिर्फ नौकरी की सोच सकते थे। स्टार्टअप इंडिया ने इसे बदल दिया। आज टीयर-2 तथा टीयर-3 शहरों और गांवों के बच्चे भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। आज 45 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक की निदेशक या सहसंस्थापक महिला है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को सरकार से साथ मिलने का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखना होगा। आप नये आइडिया पर काम करें, समाधान खोजने पर काम करें। आप विनिर्माण पर फोकस करें। आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है। हमारा लक्ष्य होना चाहिये कि आने वाले 10 साल में भारत नये स्टार्टअप ट्रेंड और प्रौद्योगिकी में दुनिया का नेतृत्व करे।

उन्होंने कहा कि पहले स्टार्टअप स्थापित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा की सोच भी नहीं सकते थे। आज 200 स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ड्रोन सेक्टर में पुराने पड़ चुके कानून हटाकर सरकार ने स्टार्टअप पर भरोसा किया। आज 35 हजार छोटी कंपनियां और स्टार्टअप जैम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

उन्होंने कहा कि पूंजी के बिना सबसे अच्छे आइडिया भी बाजार तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए सरकार ने स्टार्टअप के लिए पूंजी की व्यवस्था की है। स्टार्टअप को विभिन्न योजनाओं के तहत सीड फंडिंग दी जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू हुआ तो देश में सिर्फ 400 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज उनकी संख्या दो लाख से अधिक हो चुकी है। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स ने अब तक 21 लाख लोगों को नौकरी दी है। वे आज 50 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

सरकार ने साल 2016 में 10 हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स बनाया था। पिछले बजट में 10 हजार करोड़ रुपये के एक और फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की गयी है। डीप टेक रिसर्च के लिए एक लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की गयी है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आत्मविश्वास से भरपूर एक नये भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है। अनुमान है कि लगभग 100 देश भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं।

महाराष्ट्र को मोदी पर भरोसा था, बाला साहेब का भी आशीर्वाद मिला... बीएमसी में जीत पर बोले सीएम फडणवीस

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। बीएमसी की 227 सीटों में से बीजेपी अपने दम पर 96 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं, 30 सीटों पर शिंदे गुट ने जीत हासिल की है। इस तरह से देखे बीएमसी की सत्ता पर कई दशक बाद बीजेपी कब्जा करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में बीएमसी समेत बाकी नगर निगमों में जीत पर प्रतिक्रिया दी है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीएमसी चुनाव में महायुति को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। सीएम ने कहा कि इस बार के चुनाव में पीएम मोदी के नाम और काम का साफ असर देखने को मिला है। पीएम के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। ये पीएम मोदी के विजन की जीत है। महाराष्ट्र को मोदी पर भरोसा था। बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद हमे मिला है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए।

दरअसल, बीएमसी को शिवसेना ठाकरे गुट का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार अभी तक के नतीजों और रुझानों से लग रहा है कि ठाकरे बंधुओं का कई दशक पुराना किला ध्वस्त हो रहा है। 227 सीटों में से शिवसेना और मनसे 100 सीट का आंकड़ा भी नहीं छु पाई हैं। दूसरी ओर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना बंपर जीत की ओर से बढ़ रही है।

नतीजों पर सवाल उठाना जनता का अपमान-शिंदे

संजय राउत के नतीजों को फर्जी बताने वाले बयान पर शिंदे हंस पड़े। उन्होंने कहा कि वे हमेशा चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। नतीजों पर सवाल उठाना जनता का अपमान है।

ठाकरे बंधुओं को जवाब मिल गया, जीत के बाद एकनाथ शिंदे

बीएमसी चुाव में जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जनता ने विकास के लिए हमें वोट किया है। इसके साथ ही ठाकरे बंधुओं को भी जवाब मिल गया है।

96 सीट पर जीत दर्ज, शिंदे शिवसेना भी आगे

अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 96 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है जबकि शिंदे गुट की शिवसेना भी 30 सीटों पर डंका बजा चुकी है। इस तरह से देखें तो बीएमसी अब पूरी तरह से महायुति के कब्जे में है। बीजेपी के लिए यह इसलिए भी बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव के बाद अब बीएमसी में ठाकरे बंधुओं का किला हिला दिया है। चुनाव से पहले बीएमसी में काबिज ठाकरे गुट की ओर से कई बड़े आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन अब सब फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ठाकरे वर्चस्व को और मजबूत करने के लिए मनसे के मुखिया राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ आ गए थे, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी मनसे का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है।

रामदास अठावले का बड़ा दावा, 'मुंबई का अगला मेयर महायुति से ही होगा'

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि मुंबई के मेयर महायुति गठबंधन से ही चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनावों में अधिकांश सीटें महायुति गठबंधन को ही मिल रही हैं। अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के भाजपा और आरपीआई (ए) के साथ गठबंधन ने उन्हें दशकों तक मुंबई में सत्ता में बने रहने में मदद की। एएनआई से बात करते हुए अठावले ने कहा कि आज महाराष्ट्र भर में नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना चल रही है। मुंबई की बात करें तो उद्धव ठाकरे 25-30 साल तक सत्ता में रहे। वे भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर सत्ता में रहे। आज भाजपा देश की नंबर एक पार्टी है।

रामदास अठावले ने कहा कि आरपीआई(ए) 2012 से उद्धव ठाकरे के साथ थी, इसीलिए वे सत्ता में बने रहे, लेकिन आज न तो भाजपा और न ही आरपीआई(ए) उनके साथ है। उद्धव ठाकरे ने अब राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया है, जिससे उन्हें कुछ मराठी भाषी क्षेत्रों में फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन अधिकतर सीटें महायुति गठबंधन के खाते में जा रही हैं। मुंबई के मेयर महायुति गठबंधन से होंगे और मराठी भाषी होंगे।

महायुति गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल है, ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि गठबंधन मुंबई के 117 वार्डों में आगे चल रहा है। मुंबई में भाजपा 86 सीटों पर आगे है, जबकि शिवसेना 31 सीटों पर आगे है। शिवसेना (यूबीटी) गठबंधन 68 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा है, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) केवल 9 सीटों पर, यूबीटी सेना 58 सीटों पर और एनसीपी (एसपी) केवल 1 सीट पर आगे है। इसी तरह, अजीत पवार की एनसीपी भी 1 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक बना हुआ है और वह केवल 10 सीटों पर ही आगे है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को बड़ा झटका : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, संसदीय जांच समिति के गठन को दी थी चुनौती

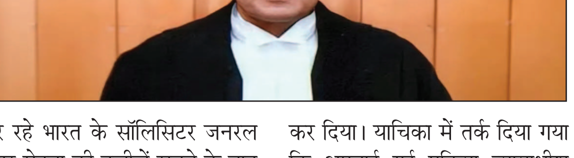

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की ओर से दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति गठित करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। यह निर्णय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर बेहिसाब नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ शुरू किए गए महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में यह समिति गठित की गई थी। न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और लोकसभा सचिवालय का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद आठ जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। न्यायमूर्ति वर्मा ने जांच समिति के गठन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि महाभियोग नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही दिन (21 जुलाई) पेश किए गए थे, फिर भी लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना या अनिवार्य संयुक्त परामर्श किए बिना एकतरफा रूप से समिति का गठन कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया कि अपनाई गई प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3(2) के विपरीत थी। इसमें धारा 3(2) के प्रावधान का हवाला दिया गया, जो यह निर्धारित करता है कि जहाँ संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव के नोटिस दिए जाते हैं, वहाँ कोई समिति तब तक गठित नहीं की जाएगी जब तक कि प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार न कर लिया जाए और यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि 21 जुलाई, 2025 को संसद के दोनों सदनों में न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग की मांग करने वाले अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए गए थे। उसी दिन, तत्कालीन राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, 11 अगस्त को राज्यसभा के उपसभापति ने उच्च सदन में पेश किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

एक दिन बाद, 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य की सदस्यता वाली एक जांच समिति के

बदायूं में बवाल : गैर समुदाय के लोगों की शिकायत पर रोकी गई प्रभात फेरी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई घायल

इस्लामनगर (बदायूं), एजेंसी। यूपी के बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम ब्योर कासिमाबाद में शुक्रवार की भोर माघ माह में निकाली जा रही प्रभात फेरी को पुलिस ने विवादित रास्ता बताते हुए रोक दिया। जबकि यह प्रभात फेरी पिछले 50 वर्षों से इसी रास्ते से निकलते आ रही है। बात इतनी बढ़ गई कि हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि लाठीचार्ज में कई ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कल दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रभात फेरी को रोकने का प्रयास किया था और पुलिस से मामले की शिकायत की थी। दूसरे समुदाय के लोगों की शिकायत के बाद शुक्रवार सुबह पांच बजे इस्लामनगर थाने की पुलिस गांव ब्योर पहुंची। इस बीच लोग प्रभात

फेरी निकालने पर अड़ गए। लोगों के गुस्से को देखकर बिल्सी, उघैती पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया। पीएसी बटालियन भी बुला ली गई। देखते ही देखते एसडीएम बिसौली राशि कृष्णा, सीओ बिल्सी मौके पर पहुंच गए। करीब आठ बजे पुलिस ने भक्तों पर लाठी चार्ज कर दिया। जिसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस के लाठीचार्ज से महिलाएं व युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे एसपी देहात हृदेश कठेरिया ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने प्रभात फेरी रोकने वाले पुलिसकर्मियों व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। काफी गहमा-गहमी के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई और प्रभात फेरी को अपने सामने ही निकलवा दिया। प्रभात फेरी निकालने के बाद भी घायल महिलाओं व युवकों के परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।

यह बोले एसपी देहात

एसपी देहात डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि प्रभात फेरी का लोग विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर प्रभात फेरी को रोका गया था, लेकिन बाद में पता चला कि प्रभात फेरी कई वर्षों से इसी रास्ते से निकलती आ रही है तो मौके पर पहुंचकर प्रभात फेरी को निकलवाया गया है। ग्रामीणों को समझा दिया गया है। प्रभात फेरी पर अब कोई रोक नहीं रहेगी।ग्रामीणों के अनुसार, गांव में कई वर्षों से प्रभात फेरी निकाली जाती रही है। लगभग दस वर्ष पूर्व सपा सरकार के समय एक समुदाय विशेष की आपत्ति के बाद प्रभात फेरी का मार्ग बदल दिया गया था। इस बार ग्रामीणों ने प्रभात फेरी पुराने मार्ग से निकालनी शुरू कर दी। इसी को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने थाना पुलिस को फोन कर आपत्ति दर्ज कराई। ग्राम ब्योर कासिमाबाद में प्रभात फेरी के मार्ग को लेकर बीते गुरुवार की भोर के समय भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। समुदाय विशेष द्वारा पुराने मार्ग से प्रभात फेरी निकाले जाने पर आपत्ति जताए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला था और प्रभात फेरी को दूसरे मार्ग से निकलवाया था।

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा- ईडी के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित

रांची, एजेंसी। ईडी और रांची पुलिस के बीच चल रहे विवाद का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रजत देते हुए रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जांच के नाम पर किसी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में बाधा नहीं डाली जा सकती। हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों में ईडी के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई से केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है, जो स्वीकार्य नहीं है। इसी आधार पर रांची पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगाई गई है।

अब ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बीएसएफ के जिम्मे होगी

इस आदेश से ईडी के उन अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अब ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बीएसएफ के जिम्मे होगी। दरअसल, ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा गुरुवार को रांची स्थित अपने कार्यालय में की गई जांच और छापेमारी के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। ईडी ने याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसी दलील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

रांची के एयरपोर्ट थाना में मामला दर्ज

इस पूरे विवाद की शुरुआत पीएचईडी (PHED) के कर्मचारी संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से हुई थी। संतोष ने आरोप लगाया था कि रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की गई। इस शिकायत के आधार पर रांची के एयरपोर्ट थाना में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

सोनू हत्याकांड पर उबाल, मेरठ कमिश्नरी पर कश्यप समाज का प्रदर्शन, मुजफ्फरनगर में हाईवे किया जाम

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ/ मुजफ्फरनगर। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में हुए सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर कश्यप समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते शुक्रवार को कश्यप समाज द्वारा मेरठ कमिश्नरी पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और जमकर प्रदर्शन किया।

महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कमिश्नरी चौराहे पर आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) की तैनाती की गई है। इसके साथ ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।

हत्या के खुलासे और गिरफ्तारी की मांग

महापंचायत में शामिल लोगों का आरोप है कि सोनू कश्यप की हत्या के मामले में अब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। कश्यप समाज ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई।

हालात पर प्रशासन की पैनी नजर

प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून हाईवे जाम

मुजफ्फरनगर में भी सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर आक्रोश देखने को मिला। कश्यप एकता क्रांति मिशन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर दिल्ली–देहरादून हाईवे पर धरना देते हुए जाम लगा दिया।

प्रदर्शनकारियों ने सोनू कश्यप के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है और आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।

दबंगों ने रास्ता रोकने पर दंपति को पीट–पीटकर किया अधमरा

» पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, आईजी से लगाई न्याय की गुहार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले के करौंदीकला थाना क्षेत्र के बूढ़ापुर गांव में दबंगई की हद पार हो गई। निजी भूमि से जबरन रास्ता निकालने का विरोध करना एक दंपति को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने पति-पत्नी को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा, पति को अधमरा कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे मजबूर होकर उन्होंने अयोध्या परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।

घटना 2 जनवरी 2026 की शाम करीब 5:30 बजे की है। पीड़िता पूनम उपाध्याय पत्नी सदाशिव उपाध्याय निवासी ग्राम बूढ़ापुर ने आरोप लगाया है कि गांव के ही जयप्रकाश, संतोष, दीपक, शनि और उनके साथी सुशील पांडेय जबरन उनकी निजी भूमि से रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। राजस्व अभिलेखों में उस स्थान पर किसी भी प्रकार का चकमार्ग या रास्ता दर्ज नहीं है। विरोध किया तो टूट पड़े दबंग जब पूनम उपाध्याय और उनके पति सदाशिव उपाध्याय ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट पर उतर आए। लात-घूंसों से की गई बर्बर पिटाई में सदाशिव उपाध्याय गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गए। हमलावर उन्हें मरा समझकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति देखी और थाने में तहरीर देने की सलाह दी। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि करौंदीकला थाने में लिखित शिकायत देने के बावजूद न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। स्थानीय स्तर पर न्याय न मिलने से आहत पीड़िता पूनम उपाध्याय ने अयोध्या परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दबंगों पर होगी कार्रवाई ?या फिर पीड़ित परिवार यूं ही न्याय के लिए भटकता रहेगा?

शाखा में लगी सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर मशीन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

जयसिंहपुर/सुल्तानपुर। लंबे इंतजार के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बरौंसा शाखा में ग्राहकों की सुविधा के लिए सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर कियोस्क स्थापित कर दिया गया है। यह पूरी तरह स्वचालित मशीन है, जिसके जरिए ग्राहक अब अपनी पासबुक स्वयं प्रिंट कर सकेंगे। मशीन की शुरुआत से जहां ग्राहकों को राहत मिलेगी, वहीं बैंक कर्मचारियों के कामकाज में भी तेजी आएगी। सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर कियोस्क पासबुक में मौजूद मैग्नेटिक स्ट्रिप/क्यूआर कोड के माध्यम से खाते की जानकारी पढ़ता है। इसके बाद खाते से जुड़े लेन-देन का पूरा विवरण स्वतः सिस्टम से प्राप्त कर पासबुक पर प्रिंट कर देता है। इसके लिए किसी कर्मचारी की मदद की आवश्यकता नहीं होगी।

गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से शाखा में पासबुक प्रिंट को लेकर ग्राहकों में असंतोष था। पासबुक अपडेट न होने के कारण ग्राहकों को लेन-देन का विवरण ई-मेल या प्रिंटेड स्टेटमेंट के रूप में लेना पड़ता था। इससे न केवल ग्राहकों को असुविधा होती थी, बल्कि कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त कार्यभार पड़ता था। शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार ने बताया कि मशीन शुक्रवार को इंस्टॉल कर दी गई है और शनिवार से यह नियमित रूप से काम करने लगेगी। उन्होंने कहा कि अब ग्राहकों को एक बार पासबुक जारी कर दी जाएगी, इसके बाद वे कभी भी मशीन के माध्यम से अपने खाते का लेन-देन स्वयं प्रिंट कर सकेंगे। शाखा प्रबंधक ने ग्राहकों से अपील की है कि स्टेपल लगी पासबुक,फटी या क्षतिग्रस्त पासबुक को मशीन में न डालें, क्योंकि इससे कियोस्क खराब हो सकता है। ग्राहक पासबुक की साफ-सफाई और सही स्थिति का विशेष ध्यान रखें। यह पहल डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और शाखा में भीड़ कम करने की दिशा में अहम कदम है। इससे समय की बचत होगी और ग्राहकों को तेज, पारदर्शी व आसान सेवा मिलेगी। सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर की शुरुआत से बरौंसा शाखा के हजारों खाताधारकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

गोरखपुर नगर निगम परिसर में बनेगा मल्टी कांप्लेक्स व मिनी ऑडिटोरियम, शासन की मंजूरी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नगर निगम परिसर में अत्याधुनिक मल्टी कांप्लेक्स और मिनी आडिटोरियम के निर्माण को शासन से मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

अनु सचिव संजय कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार परियोजना को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त की धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इससे नगर निगम परिसर और शास्त्री चौक क्षेत्र के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है।

योजना के अनुसार इस परियोजना पर कुल 3477.33 लाख रुपये, यानी 34 करोड़ 77 लाख 33 हजार रुपये की लागत आएगी। शासन ने प्रथम किस्त के रूप में कुल लागत का 35 प्रतिशत, यानी 1217.06 लाख रुपये (12 करोड़ 17 लाख 6 हजार रुपये) जारी कर दिए हैं। इसके बाद जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टेंडर के पश्चात शास्त्री चौक क्षेत्र में बड़े स्तर पर पुनर्विकास और ध्वस्तीकरण का कार्य आरंभ होगा।

निर्माण की जद में आएंगी 32 दुकानें

इस परियोजना के अंतर्गत शास्त्री चौक पर स्थित नगर निगम की दुकानें, मेडिकल स्टोर, ट्रांसपोर्ट कार्यालय, रेस्टोरेंट, होटल मयूर, विद्युत नगरीय वितरण खंड कार्यालय, चंद्रलोक लाज व होटल सहित कई पुरानी दुकानें ध्वस्तीकरण की जद में आएंगी। हालांकि निर्माण प्रक्रिया के दौरान विद्युत सब स्टेशन के हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा न आए।

> मिनी ऑडिटोरियम के निर्माण संबंधी शासनादेश जारी हो गया है। जल्द ही टेंडर और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह परियोजना शहर के विकास को नई दिशा देगी।
>
> **-अमित कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम**

इस पुनर्विकास से प्रभावित होने वाले कुल 32 नगर निगम आवंटियों को नए बनने वाले मल्टी कांप्लेक्स में प्राथमिकता के आधार पर दुकानें आवंटित की जाएंगी। इससे उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और वे आधुनिक सुविधाओं के साथ अपना कार्य जारी रख सकें।

योजना के अनुसार मल्टी कांप्लेक्स को पूरी तरह व्यावसायिक और सुविधाजनक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। इसके बेसमेंट में 28 कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। भूतल पर 16 दुकानें बनाई जाएंगी, जबकि प्रथम तल पर 10 आधुनिक आफिस स्पेस विकसित किए जाएंगे। द्वितीय तल पर 261 दर्शकों की क्षमता वाला अत्याधुनिक मिनी आडिटोरियम बनेगा, जो पूरी तरह साउंड प्रूफ और वातानुकूलित होगा। इसमें दर्शकों के लिए 261 आरामदायक कुर्सियां लगाई जाएंगी।

परियोजना में पर्यावरण संरक्षण को भी विशेष महत्व दिया गया है। वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी और 150 किलोलीटर क्षमता का भूमिगत जल टैंक बनाया जाएगा।

स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन पर आधारित वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित तथा जिलाधिकारी कुमार हर्ष और मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, करौंदिया में विज्ञान लोक प्रियकरण एवम् संचार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन पर आधारित वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सह विद्यालय निरीक्षक जटा शंकर यादव, प्रसिद्ध सर्जन डॉ रमेश ओझा, एस बी यादव, चिकित्सक डॉ मनीष श्रीवास्तव, रिसोर्स पर्सन अंजली ढाका, जिला समन्वयक अखिलेश पांडे, शैलेन्द्र चतुर्वेदी समेत कई अतिथि उपस्थित थे। सर्वप्रथम सभी अतिथियों को शुभतिलक लगाकर एवम् बैज पहनाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती व बाबू के एन सिंह जी की प्रतिमा पर

माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। सह जिला विद्यालय निरीक्षक जटाशंकर यादव ने आज के आधुनिक विज्ञान तथा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान के विभिन्न खोजों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य एल 1 आदि विभिन्न प्रकार की खोजों में हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने डॉ अब्दुल कलाम जी के साथ दूसाथ विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में भी बच्चों को बताया। राजकीय इण्टर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एस बी यादव ने बच्चों को पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमारे वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के बारे में भी बताया जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण को स्वच्छ व सुरक्षित रखने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमें पेड़ की कटान को रोकना चाहिए तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए।हमें अपनी नदियों को भी प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से होने वाली हानियों के बारे में भी बताया। उन्होंने अन्त में पर्यावरण और जीवन को बचाने के लिए प्रेरित किया।मेरठ से आई रिसोर्स पर्सन अंजली ढाका ने घनत्व मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले लैक्टोमीटर का टेस्ट ट्यूब द्वारा दूध पर प्रयोग करके तथा फास्ट फूड को विस्तार से समझाया तथा बी एम आई के कैलकुलेशन को समझाया। तत्पश्चात प्योर हल्दी के बारे में परीक्षण करके विस्तार से बताया।इस अवसर पर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा अंग्रेजी के मॉडल व पोस्टर तथा स्लोगन प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। कार्यक्रम के अन्त में राष्ट्रपति पुरस्कार तथा डेरेजियो पुरस्कार से पुरस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ एन डी सिंह ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।इस अवसर पर विद्यालय की समन्वयक रेनू सिंह,रसायन विज्ञान के प्रवक्ता सिद्धांत कुमार सिंह, भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा तथा जीव विज्ञान की प्रवक्ता वागीशा मिश्रा समेत सभी शिक्षक दृशिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

वाराणसी–रीवां हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार बाइक, एक युवक की दर्दनाक मौत

आर्यावर्त संवाददाता

लालगंज (मीरजापुर)। वाराणसी-रीवां हाईवे पर बुधवार की रात करीब दस बजे हुए सड़क हादसे में प्रयागराज के रहने वाले युवक की मौत हो गई। बाइक सवार युवक चिरुईराम गांव स्थित पानी टंकी के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ गया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराकर इसकी सूचना स्वजन को दी।

प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र के मड़फा कला गांव निवासी 21 वर्षीय संतोष कुमार बाइक से लालगंज के लहंगपुर स्थित रेही गांव के रहने वाले एक रिश्तेदार के यहां आयोजित बरही के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह आए थे। कार्यक्रम में शामिल होकर रात में बरौंधा की ओर से लालगंज होते हुए प्रयागराज जा रहे थे।

चेरूईराम गांव के पास पहुंचे तो खड़े ट्रक में टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि संतोष गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले गई। वहां चिकित्सकों ने देखने के बाद संतोष को मृत घोषित कर दिया।

लालगंज के प्रभारी निरीक्षक अभय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। संतोष कुमार दो बहनों व दो भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। वह पुणे की एक कंपनी में काम करते थे। इन दिनों घर आए हुए थे।

गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी यूपी की तस्वीर, मेरठ से प्रयागराज का सफर सिर्फ 6 से 7 घंटे में

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के मेरठ से लेकर प्रयागराज तक सीधा संपर्क स्थापित करेगा। 594 किलोमीटर लंबा यह सफर अब महज 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा।

मेरठ बिजौली से शुरू, खड़खड़ी में टोल प्लाजा तैयार

गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ के बिजौली क्षेत्र से हुई है। खड़खड़ी में टोल प्लाजा बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि एक्सप्रेसवे से जुड़े कई स्थानों पर सर्विस रोड का कार्य अभी अधूरा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष भी है।

किसानों की जिंदगी और रहन-सहन में आया बदलाव

गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर समेत कई जिलों के किसानों की दिनचर्या और रहन-सहन में बड़ा बदलाव आया है। भूमि के दाम बढ़े हैं और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं।

औद्योगिक गलियारे से वैश्विक पहचान

एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही गंगा एक्सप्रेसवे विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाएगा और निवेशकों को आकर्षित करेगा।

हाईटेक सुविधाओं से लैस एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति से वाहन दौड़ सकेंगे। सुरक्षा के लिए हाई पावर कैमरे, स्ट्रीट लाइट्स और अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। खास बात यह है कि आपात स्थिति में एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज भी उतारे जा सकेंगे।

जनता को शुभारंभ का इंतजार

स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनता को दिया गया एक बड़ा तोहफा है। अब सभी को इसके औपचारिक शुभारंभ का बेसब्री से इंतजार है।

महिला अस्पताल में प्रसूता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले में एक महिला की प्रसव के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना जिला अस्पताल में हुई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों और कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही तथा बदसलूकी का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी बेटी की जान गई। मृतका अंशिका उपाध्याय (24 वर्ष) पत्नी पंकज उपाध्याय कादीपुर कोतवाली के पदारथपुर की रहने वाली थीं। उनका विवाह बीते 5 मई 2025 को हुआ था। मृतका की मां उर्मिला पांडे ने बताया कि वे अंशिका को कल दोपहर 12 बजे अस्पताल लेकर आए थे। जांच में खून 11 पॉइंट था और सब कुछ सामान्य था। शाम 6:24 बजे अंशिका ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद डॉक्टरों ने उसे वैसे ही

छोड़ दिया। रात 9:30 बजे टांके लगाए गए और रात 10:30 बजे उसे अंदर ले जाया गया। उर्मिला पांडे के अनुसार, अंशिका ने उन्हें बताया कि उसे बहुत ठंड लग रही है और वह कांप रही थी। परिजनों ने बार-बार डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन वे सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करके चले जाते थे। सुबह 4:30 बजे जब अंशिका की सांसें उखड़ने लगीं, तब डॉक्टरों ने उसे कहीं और ले जाने को कहा। परिजनों ने सवाल उठाया कि यह बात पहले क्यों नहीं बताई गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो छह महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मोबाइल छीनने का प्रयास किया और परिजनों व उनके रिश्तेदारों के साथ मारपीट भी की। परिजनों ने डॉक्टरों, गार्डों और पोस्टमार्टम स्टाफ के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने यह भी बताया कि प्रशासन ने बिना उन्हें सूचित किए अंशिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी बेटी ने न तो जहर खाया था और न ही उसे कोई बीमारी थी, यह पूरी तरह से डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है। मामले में सीएमएस महिला डॉ. आरके यादव ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं, नगर कोतवाल धीरज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री का सख्त संदेश, पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार पर होगी कठोर कार्रवाई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मकर संक्रांति और खिचड़ी महापर्व के दौरान लगातार दो दिनों तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं की निगरानी में सक्रिय रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया। जनता से सीधे संवाद के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी व संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए।

गोरखनाथ मंदिर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। वे स्वयं कुर्सियों पर बैठे लोगों तक पहुंचे, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।जनता दर्शन में भूमि पट्टा आवंटन से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री विशेष रूप से गंभीर नजर आए। एक महिला द्वारा गांव में गरीबों को जमीन का पट्टा देने में अनियमितता और रुपये लेकर पट्टा बांटने की शिकायत किए जाने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी इस प्रकार की शिकायतें मिलें, वहां तत्काल जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।अपराध से संबंधित मामलों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई ढिलाई न बरती जाए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए।

जनता दर्शन के दौरान एक महिला द्वारा आर्थिक तंगी के कारण बेटी की शादी को लेकर चिंता जताए जाने पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों से कहा कि बिटिया का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े।गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंद मरीजों के उच्चस्तरीय उपचार का एस्टीमेट तत्काल तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार की ओर से इलाज के लिए आवश्यक धनराशि तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।जनता दर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि शासन-प्रशासन आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य कर रहा है और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विश्वविद्यालय एक खेल गोद लें, खेलों से निखरेगा युवा और साकार होगा विकसित भारत : मुख्यमंत्री योगी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को चाहिए कि वे किसी एक खेल को गोद लेकर उससे जुड़ी प्रतिभाओं को निखारें। खेलों के माध्यम से युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और खेल भावना का विकास होगा, जिससे वे नशे और सामाजिक विकृतियों से दूर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा खेलेगा तो खिलेगा और यही सशक्त युवा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के औपचारिक उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह चरित्र निर्माण, आत्मअनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त जरिया हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देकर ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश खेलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित की जा चुकी है और मेरठ आज खेल सामग्री निर्माण का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जिसे सरकार ने ओडीओपी योजना से जोड़ा है। इससे युवाओं को खेल के साथ रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते 11 वर्षों में देश में एक नई खेल संस्कृति का विकास हुआ है। वर्ष 2014 से पहले खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा होती थी, जबकि आज खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेल प्रतियोगिता जैसे अभियानों ने गांव-गांव तक प्रतिभाओं को पहचान और मंच दिया है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि ऋषि परंपरा का उद्घोष 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी साधन प्राप्त किए जा सकते हैं। खेलों से जुड़कर नियम, संयम और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। उन्होंने संतोष जताया कि आज समाज में बेटा-बेटी के बीच भेदभाव कम हो रहा है और अभिभावक बच्चों की खेल प्रतिभा को पूरे मन से प्रोत्साहित कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया है। हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान और ओपन जिम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम तथा जिला स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। खेलों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 96 हजार से अधिक युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट वितरित की गई हैं।

'उत्तर प्रदेश को देश का खाद्य प्रसंस्करण हब बनाने का संकल्प, इंडिया फूड एक्सपो से युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा नया मंच'

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण हब बनाया जाना है और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं, किसानों और उद्यमियों से आह्वान किया कि वे इंडिया फूड एक्सपो–2026 जैसे आयोजनों का भरपूर लाभ उठाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति देश की सबसे बेहतर नीतियों में से एक है और विकसित भारत के प्रधानमंत्री के विजन को हर हाल में पूरा करना हम सभी का संकल्प है।उप मुख्यमंत्री गोमती नगर स्थित रिगेलिया ग्रीन्स में आयोजित तीन दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो एवं सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने एक्सपो और प्रदर्शनी का उद्घाटन कर स्टॉलों का अवलोकन किया तथा इंडस्ट्रियल डायरेक्ट्री का विमोचन भी किया। इस अवसर पर पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले डीआरपी, बैंकर्स, उद्यमियों और लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही पांच उद्यमियों को एलओसी और सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किए गए।सेमिनार को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। उत्पादन, तकनीक, ब्रांडिंग और उपभोक्ताओं के बेहतर जुड़ाव के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि भारत को दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत है और औद्योगिक निवेश के लिए यहां अनुकूल वातावरण है। युवाओं, उद्यमियों और किसानों के लिए यह समय ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है।उन्होंने बताया कि प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति में महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। महिलाओं द्वारा लगाए गए उद्यमों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। स्वच्छ भारत–स्वस्थ भारत की भावना को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की फसल किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। किसान, उद्यमी और उपभोक्ता के बीच एक मजबूत चेन तैयार करनी होगी। इस दिशा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में देश और प्रदेश लंबी छलांग लगा रहे हैं और इंडिया फूड एक्सपो जैसे आयोजन किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए असीम संभावनाएं हैं। यह एक्सपो विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित करना है। किसान, युवा, महिला समूह और उद्यमी सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।

मुंशीपुलिया लखनऊ व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों को दिलाया भरोसा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। शुक्रवार को मुंशीपुलिया चौराहे पर मुंशीपुलिया लखनऊ व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। समारोह में बड़ी संख्या में व्यापारी, पदाधिकारी और संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे, जिससे यह आयोजन व्यापारिक एकता और संगठन की मजबूती का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम का संचालन अरविन्द पाठक ने किया। उन्होंने मंच से जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता सहित अरविन्द पाठक, हिमांशु भट्ट, परमजीत सिंह, अभिषेक सिंह चौहान, मुकेश सिंह, रिंकू यादव, विशाल चौरसिया, बी.बी. सिंह, महेश शर्मा और रवि मिश्रा मंचासीन रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक का अंगवस्त्र, मोमेंटो एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा मुंशीपुलिया लखनऊ व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नितिन जैन को सौंपी गई, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक गुप्ता और अनुज सिंह बने। कोषाध्यक्ष पद पर एस.पी. मिश्रा तथा उपाध्यक्ष पद पर एस.एस. यादव (एडवोकेट), ओम प्रकाश सिंह, पी.के. श्रीवास्तव, ललित राजपाल, अनिल अग्रवाल, राहुल कुमार जायसवाल और संदीप जायसवाल को दायित्व सौंपा गया। वरिष्ठ संगठन मंत्री आर्क चंदन सिंह, संगठन मंत्री दीपक तिवारी (एडवोकेट) और विनीत जैन बनाए गए। विधि सलाहकार के रूप में सुभाष चंद्रा (एडवोकेट) और अनिल तिवारी (एडवोकेट) को जिम्मेदारी दी गई, जबकि मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन बनाए गए। इसके अलावा रामशंकर गुप्ता, राहुल अग्रवाल, गुलशन कुमार जसवानी, अजित यादव, अनुराग मिश्रा और मोमिन सिद्दीकी को मंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान अयोध्या रोड क्षेत्र के पवन सिंह और आदर्श प्रताप सिंह को लखनऊ व्यापार मंडल की सदस्यता दिलाई गई। अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र की उपस्थिति में पवन सिंह को उपाध्यक्ष और आदर्श प्रताप सिंह को संगठन मंत्री घोषित किया गया, जिन्हें उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापार और उद्योग किसी भी समाज की आर्थिक रीढ़ होते हैं। लखनऊ व्यापार मंडल जैसे संगठन व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा, उनकी सुरक्षा और व्यापार को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि छोटे और मध्यम व्यापारी बिना किसी भय के अपना व्यवसाय कर सकें। लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि व्यापार मंडल केवल एक संगठन नहीं, बल्कि व्यापारियों के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की मजबूत आवाज है। शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से एक सशक्त, जिम्मेदार और समर्पित टीम का गठन हुआ है, जो पूरी निष्ठा से व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगीअध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि लखनऊ व्यापार मंडल व्यापारियों की एकता, सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत रहा है। समारोह में व्यापारियों की एकजुट भागीदारी यह दर्शाती है कि संगठन दिन-प्रतिदिन और अधिक मजबूत हो रहा है। कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस शपथ ग्रहण समारोह से संगठन को नई ऊर्जा मिली है और नवनियुक्त पदाधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करेंगे। इंदिरानगर परिक्षेत्र प्रभारी हिमांशु भट्ट ने बताया कि संगठन का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र के व्यापारियों को संगठित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराना है। उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह चौहान ने संगठन को व्यापारियों की एकजुटता और अधिकारों की मजबूत आवाज बताया, जबकि युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि युवा व्यापारियों की भागीदारी से संगठन को नई सोच और नई दिशा मिलती है। अंत में अध्यक्ष नितिन जैन और वरिष्ठ महामंत्री अभिषेक गुप्ता ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा व्यापारियों के हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों की उपस्थिति रही, जिससे यह शपथ ग्रहण समारोह व्यापारिक एकता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश देता नजर आया।

जोन–6 में अवैध डेयरियों पर नगर निगम का सख्त अभियान, 20 पशु जब्त, विरोध के बीच कार्रवाई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। शहरी स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ ने शुक्रवार को जोन-6 के पारा थाना क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में यह विशेष कार्रवाई की गई, जिसमें पारा थाना क्षेत्र की पिंक सिटी कॉलोनी और सूर्य नगर में संचालित अवैध डेयरियों को निशाने पर लिया गया। कार्रवाई के दौरान डेरी संचालकों द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ अभियान को अंजाम दिया।अभियान के दौरान कुल 11 भैंस, एक पड़िया और आठ गाय जब्त की गईं। जब्त किए गए सभी पशुओं को पीजीआई स्थित कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया है, जहां से इन्हें निर्धारित जुर्माना जमा करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। यह कार्रवाई स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के आधार पर की गई थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अवैध डेयरियों के संचालक गोबर को खुले प्लॉटों में फेंक रहे हैं और नालियों में बहा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी, जलभराव और मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।नगर निगम ने स्पष्ट किया कि नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत शहरी सीमा में भैंस पालन पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इसे अपदूषण कारक पशु की श्रेणी में रखा गया है। नियमों के अनुसार केवल अधिकतम दो गायों को ही वैध लाइसेंस के तहत पालने की अनुमति है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से डेयरियों का संचालन किया जा रहा था।

शहरी विकास योजनाओं में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं, परिणाम जमीन पर दिखने चाहिए : ए.के. शर्मा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार, लखनऊ में नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और इनमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं की प्रगति केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसके परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन, गौशाला, डॉग शेल्टर, आकांक्षी नगर योजना, वैश्विक नगरोदय योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, सीएम ग्रिड योजना, स्मार्ट पालिका, पंडित दीनदयाल नगरीय विकास योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में कार्य की गति तेज की जाए और समयबद्ध ढंग से उन्हें पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।आवासीय योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर मंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय योजनाएं आम नागरिकों से सीधे जुड़ी होती हैं, ऐसे में इनमें किसी भी प्रकार की देरी जनहित के विपरीत है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम ग्रिड योजना को पालिका स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि यह योजना शहरी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगी।मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाएं। निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाकर योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।बैठक में जल निकासी व्यवस्था, झील, तालाब, पोखर, वंदन एवं अंत्येष्टि स्थलों से जुड़े कार्यों में पुनर्विनियोग करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कैडर रिव्यू और विभागीय कार्यवाहियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने इन मामलों में भी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।इस समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद, सचिव एवं निदेशक नगरीय निकाय अनुज झा, सचिव एवं एमडी जल निगम रविंद्र कुमार प्रथम, विशेष सचिव सूडा एवं जेएमडी जल निगम प्रवीण लक्ष्यकार, विशेष सचिव

जोन–1 के कई वार्डों में औचक निरीक्षण, गंदगी और लापरवाही पर सख्त रुख, दोषियों पर जुर्माना व वेतन कटौती के निर्देश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने महापौर सुषमा खर्कवाल के साथ जोन-1 अंतर्गत विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था, जल निकासी और नगर निगम के कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि शहर की साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण की शुरुआत विक्रमादित्य महात्मा गांधी वार्ड स्थित योजना भवन, डायमंड डेरी, उदयगंज से हुई, जहां नालियों की गंदगी और क्षेत्र में फैली अव्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। मौके पर ही तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए। सड़क पर मलबा और कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए गए, ताकि स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। इसके बाद डायमंड डेरी के पास स्थित पंपिंग स्टेशन के आसपास निरीक्षण किया गया, जहां वर्षों से खाली पड़े एक प्लॉट में जमा मलबे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए और प्लॉट मालिक के विरुद्ध जुर्माना लगाने के कड़े आदेश जारी किए गए।इसके पश्चात जोन-1 के बाबू बनारसी दास वार्ड में निरीक्षण के दौरान हैदर कैनाल की रिटेनिंग वॉल की मरम्मत कराने और उसके आसपास समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। लालकुआं वार्ड में निरीक्षण के दौरान नालियों की सफाई, कूड़े के नियमित उठान और नालियों से होकर गुजर रही पेयजल पाइपलाइन को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त पाइपलाइन को शीघ्र स्थानांतरित किया जाए, ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम समाप्त हों।नज़रबाग वार्ड के सुंदरबाग क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान नालियों की सफाई और कूड़ा उठान में लापरवाही पाए जाने पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए जोनल अधिकारी से लेकर अधीनस्थ स्तर तक के अधिकारियों के दो दिन के वेतन की कटौती के निर्देश दिए। जेसी बोस वार्ड में निरीक्षण के दौरान नालियों की समुचित सफाई, क्षेत्र में यूरिनल निर्माण और सीवर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।पूरे निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाएं शासन की प्राथमिकता हैं और इसमें कोताही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के समय नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त सहित नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि कुछ वार्डों में संबंधित पार्षद भी निरीक्षण दल के साथ उपस्थित रहे।

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में "फ्लाई हाई, से नो टू रैगिंग" संदेश के साथ पतंग उड़ान प्रतियोगिता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में "फ्लाई हाई, से नो टू रैगिंग" विषय पर आयोजित पतंग उड़ान प्रतियोगिता का सफल और उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच आपसी सद्भाव, सकारात्मक सोच और रैगिंग के विरुद्ध जागरूकता को मजबूत करना था। प्रतियोगिता के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वस्थ, सुरक्षित और सहयोगपूर्ण शैक्षणिक वातावरण ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. राम चंद्रा, प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अमित सिंह, प्रो. नरेन्द्र कुमार तथा आयोजन समिति के संयोजक डॉ. मनोज कुमार डडवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक और सहभागितापूर्ण आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। तथा

ऑपरेशन पहचान के तहत लखनऊ में किरायेदार पंजीकरण अभियान तेज, वर्ष 2025 में 13,864 रजिस्ट्रेशन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन पहचान' के अंतर्गत किरायेदार पंजीकरण अभियान को व्यापक स्तर पर लागू किया गया है। इस अभियान के तहत वर्ष 2025 के दौरान लखनऊ के विभिन्न जोनों में कुल 13,864 किरायेदारों का पंजीकरण किया गया है, जिनका संबंधित थानों की पुलिस टीमों द्वारा लगातार भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है।पुलिस कमिश्नरेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में मध्य जोन में 843, पूर्वी जोन में 6657, दक्षिणी जोन में 4928, पश्चिमी जोन में 532 तथा उत्तरी जोन में 904 किरायेदारों का पंजीकरण कराया गया। पुलिस का कहना है कि किरायेदारों का समय से पंजीकरण और सत्यापन अपराध नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी कदम है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।मकान मालिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किरायेदार पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया गया है। इसके लिए लखनऊ पुलिस की आधिकारिक वे ब सा इ ट lucknowpolice.up.gov.in और UPCOP APP पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मकान मालिक का यह दायित्व है कि वह अपने यहां रहने वाले किरायेदार की पूरी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से पुलिस को उपलब्ध कराए। यह प्रक्रिया किरायेदार को मकान या संपत्ति किराये पर देने से पहले अथवा अधिकतम एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।पुलिस के अनुसार यदि किसी मकान में एक से अधिक किरायेदार निवास कर रहे हैं, तो सभी का पंजीकरण और सत्यापन कराना आवश्यक है। पंजीकरण के उपरांत संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें मकान मालिकों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है। साथ ही मकान मालिकों को किरायेदार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मूल पता अपने पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।पुलिस कमिश्नरेट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी किरायेदार की संलिप्तता आपराधिक गतिविधियों में पाई जाती है और उस किरायेदार की सूचना पहले से पुलिस को नहीं दी गई होती है, तो संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि किसी विदेशी नागरिक को मकान किराये पर दिया जाता है, तो मकान मालिक को अनिवार्य रूप से फॉर्म-सी भरकर स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी।ऑपरेशन पहचान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में लगातार जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के वार रूम में क्या चल रहा है? किन देशों के नाम लाल घेरे में हैं?

आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के वार रूम में इस समय क्या चल रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर कौन से देश के नक्शे खुले हैं, किन देशों के नाम लाल घेरे में हैं और किन मोर्चों पर सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी हो रही है। देखा जाये तो अमेरिकी राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयानों, नीतिगत संकेतों और सैन्य गतिविधियों से साफ झलकता है कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। आइये आज इसी पर बात करते हैं और आपको तथ्यों के साथ पूरी जानकारी देते हैं कि ट्रंप के निशाने पर इस समय कौन कौन से देश हैं और उनके खिलाफ अमेरिका किस स्तर की तैयारी कर रहा है। देखा जाये तो साल 2026 की शुरुआत वैश्विक राजनीति के लिए एक बेचैन करने वाला संकेत लेकर आई है। दुनिया के नक्शे पर अमेरिका एक बार फिर उस भूमिका में दिख रहा है जिसे वह शीत युद्ध के दौर में निभाता था यानी निर्णायक दबाव डालने वाला सर्वशक्तिमान केंद्र। इस बार मंच पर हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी भाषा पहले से अधिक तीखी, अधिक उकसाने वाली और अधिक विस्फोटक बनी हुई है। सबसे पहले वेनेजुएला की बात करें तो आपको बता दें कि ट्रंप ने खुद को सार्वजनिक रूप से वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मर्यादा को जानबूझकर तोड़ा है। इसका सीधा संदेश यह है कि अमेरिका अब वेनेजुएला को एक संप्रभु राष्ट्र की तरह नहीं बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र के एक प्रशासित इलाके की तरह देख रहा है। देखा जाये तो वेनेजुएला का सामरिक महत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ऊर्जा पर आधारित है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर नियंत्रण का अर्थ है वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव। ट्रंप का खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताना दरअसल यह बताने का तरीका है कि अमेरिका वहां सत्ता परिवर्तन को अब छिपाकर नहीं बल्कि खुले तौर पर संचालित करना चाहता है। यह सीधे तौर पर संसाधन नियंत्रण की राजनीति है। इसी कड़ी में क्यूबा को लेकर ट्रंप का रवैया भी ध्यान खींचता है। क्यूबा को तेल आपूर्ति रोकने की धमकी और उसके बाद यह कहना कि मार्को रुबियो का क्यूबा का राष्ट्रपति बनना उन्हें ठीक लगता है, यह सब मजाक नहीं है। यह एक राजनीतिक संदेश है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अब वैचारिक असहमति को सहन करने के मूड में नहीं है। वह खुले तौर पर यह संकेत दे रहा है कि जो सरकारें उसकी लाइन पर नहीं चलेंगी, उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से कुचल दिया जाएगा। देखा जाये तो मार्को रुबियो का नाम लेना प्रतीकात्मक है। एक ऐसा नेता जिसकी पहचान क्यूबा विरोधी राजनीति से जुड़ी रही है, उसे वहां के राष्ट्रपति पद से जोड़ना यह बताता है कि अमेरिका लोकतंत्र नहीं बल्कि अपने हितों के प्रति वफादार शासन चाहता है। यह बयान भले ही अनौपचारिक हो लेकिन इसके निहितार्थ बेहद गहरे हैं।

ईरान की बात करें तो आपको बता दें कि ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका ईरान के लिए बहुत मजबूत सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। देखा जाये तो यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है क्योंकि अमेरिका इस समय फारस की खाड़ी से लेकर पश्चिम एशिया तक अपनी सैन्य तैनाती मजबूत कर रहा है। हवाई हमलों से लेकर साइबर और ड्रोन हमलों तक की तैयारी की जा रही है। सवाल यह नहीं है कि हमला होगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि हमला कब और कितना बड़ा होगा? देखा जाये तो यदि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके परिणाम केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वैश्विक आपूर्ति शृंखला टूट सकती है। मुस्लिम देशों का रुख इस मामले में एक जैसा नहीं होगा। कुछ देश रणनीतिक मजबूरी में अमेरिका का सीमित समर्थन कर सकते हैं, लेकिन व्यापक इस्लामी दुनिया में इसका तीखा विरोध होगा। यह टकराव क्षेत्रीय से वैश्विक संकट में बदल सकता है। ईरान पर हमले का एक और परिणाम होगा प्रतिशोध। ईरान सीधे या परोक्ष रूप से अपने सहयोगी संगठनों के जरिये जवाब देगा। इसका असर इजरायल से लेकर खाड़ी देशों तक दिख सकता है। इस तरह यह संघर्ष किसी एक मोर्चे पर सीमित नहीं रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका की वैश्विक दादागिरी साफ दिखाई दे रही है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का यह कहना कि अमेरिका ने यदि उस क्षेत्र को नहीं लिया तो उसे चीन या रूस ले लेंगे, यह दर्शाता है कि अमेरिका दुनिया को अब भी एक शतरंज की बिसात मानता है जहां मोहरे उसकी मर्जी से हिलने चाहिए। यह मानसिकता बताती है कि बहुध्रुवीय दुनिया की सच्चाई को स्वीकार करने में अमेरिका अब भी असहज है।

मोदी ने दिल्ली में और शाह ने तमिलनाडु में पोंगल मना कर बड़ा राजनीतिक एंगल सेट कर दिया है

नीरज कुमार दुबे

देशभर में पोंगल पर्व पूरे उत्साह और परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तमिल समुदाय के साथ पोंगल मनाया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले सप्ताह अपनी तमिलनाडु यात्रा के दौरान पोंगल समारोहों में शामिल हुए थे। दोनों नेताओं की मौजूदगी ने इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक तो बनाया ही साथ ही आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को देखते हुए इसे राजनीतिक रूप से भी चर्चा के केंद्र में ला दिया।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भाग लिया। पारंपरिक अंदाज में हुए इस आयोजन में तमिल रीति-रिवाजों के अनुसार पोंगल पकाया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पोंगल केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की विविध संस्कृतियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और तमिल संस्कृति उसकी अमूल्य धरोहर है। मोदी ने तमिल भाषा और परंपराओं की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्कृति आज वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना रही है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, जल-संरक्षण और मिट्टी की सेहत को बनाए रखने की जरूरत पर भी बात की और कहा कि पोंगल का संदेश हमें सतत जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा देता है।

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा-अर्चना की और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद वह स्थानीय स्तर पर आयोजित पोंगल समारोहों में शामिल हुए, जहां पारंपरिक वेशभूषा, लोक-संस्कृति और ग्रामीण परिवेश में उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि पोंगल तमिल समाज की आत्मा से जुड़ा पर्व है, जो किसान, परिश्रम और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने तमिल संस्कृति की जीवंतता की सराहना करते हुए कहा कि भारत की विविधता ही उसकी एकता का आधार है। गृह मंत्री ने स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया और पोंगल की शुभकामनाएं दीं।

देखा जाये तो दिल्ली और तमिलनाडु में पोंगल उत्सवों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की सहभागिता ने यह रेखांकित किया कि भारत की विविध संस्कृतियां एक-दूसरे से जुड़कर देश की साझा विरासत को मजबूत करती हैं। पोंगल न केवल फसल उत्सव रहा, बल्कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त करने वाला अवसर भी साबित हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में पोंगल मनाना और अमित शाह का तमिलनाडु पहुंचकर उसी पर्व को पूरे धार्मिक, सांस्कृतिक रंग में मनाना, केवल संयोग भर नहीं लगता। यह साफ तौर पर एक सुविचारित राजनीतिक संकेत है, जिसे समझने के लिए तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन और वहां की संवेदनशीलताओं को जानना जरूरी है।

दरअसल, पोंगल तमिल अस्मिता का केंद्रबिंदु है, यह खेती, सूर्य, प्रकृति और श्रम के सम्मान का पर्व है। लंबे समय से तमिल राजनीति में यह धारणा मजबूत रही है कि राष्ट्रीय दल, खासकर भाजपा, तमिल संस्कृति को या तो हाशिये पर रखती है या उसे केवल चुनावी अवसरों पर याद करती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का दिल्ली में तमिल परंपरा के अनुसार पोंगल मनाना और तमिल संस्कृति को "वैश्विक मानव विरासत" के रूप में प्रस्तुत करना, उसी धारणा को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।

दूसरी ओर, अमित शाह का तमिलनाडु में मंदिरों में पूजा, पारंपरिक वेशभूषा में पोंगल समारोहों में शामिल होना और स्थानीय आयोजनों में सक्रिय भागीदारी, भाजपा की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें राजनीति को संस्कृति के रास्ते समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वही मॉडल है जिसे पार्टी उत्तर और पश्चिम भारत में सफलतापूर्वक आजमा चुकी है यानि स्थानीय परंपराओं को अपनाइए, उन्हें राष्ट्रीय विमर्श से जोड़िए और फिर राजनीतिक विश्वास की जमीन तैयार कीजिए।

हालांकि सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु की जनता इसे केवल सांस्कृतिक सम्मान के रूप में देखेगी या चुनावी अवसरवाद के तौर पर? तमिल राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां की जनता प्रतीकों से अधिक नीतियों, भाषा के सम्मान और संघीय अधिकारों के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देती है। पोंगल मनाना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसके साथ-साथ तमिल भाषा, राज्य के अधिकारों और केंद्र-राज्य संबंधों पर ठोस भरोसा पैदा करना भी उतना ही जरूरी है।

बहरहाल, मोदी और शाह का पोंगल उत्सव एक राजनीतिक संवाद की शुरुआत है। यह भाजपा की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वह तमिलनाडु में "बाहरी पार्टी" की छवि से बाहर निकलकर खुद को स्थानीय संस्कृति के साथ खड़ा दिखाना चाहती है। लेकिन चुनावी मैदान में यह रणनीति तभी सफल होगी, जब सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ-साथ भरोसेमंद राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा भी जमीन पर उतरे। पोंगल की मिठास से शुरुआत हो चुकी है, अब देखना यह है कि क्या यह मिठास तमिलनाडु की राजनीति में स्थायी स्वाद छोड़ पाएगी या केवल चुनावी मौसम की खुशबू बनकर रह जाएगी।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भाग लिया। पारंपरिक अंदाज में हुए इस आयोजन में तमिल रीति-रिवाजों के अनुसार पोंगल पकाया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

टिप्पणी

हमले से अधिकांश देशों के कान खड़े

ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के खिलाफ जो तर्क दिया है, आशंका है कि वह वैसी ही दलील ग्रीनलैंड, क्यूबा, मेक्सिको और यहां तक कि कनाडा के खिलाफ भी गढ़ सकता है। इसीलिए इस हमले से अधिकांश देशों के कान खड़े हुए हैं।

डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के आसपास सैन्य दबाव कई महीनों से बना रखा था, लेकिन तब कहा गया कि यह 'मादक पदार्थों की तस्करी' पर कार्रवाई के लिए है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने अपने देश की संसद के सामने कहा कि वेनेजुएला पर हमला करने या वहां 'शासन परिवर्तन' कराने का उसका कोई इरादा नहीं है। इस तरह तीन जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर जो हमला किया, वह अमेरिका में बिना संसदीय मंजूरी के किया गया। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के अनेक सांसदों ने इसे अमेरिकी संविधान का उल्लंघन बताया है।

इस हमले के जरिए वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकलस मदुरो और उनकी पत्नी को उनके निवास से उठा लिया गया। उन्हें न्यूयॉर्क लाकर उन पर मुकदमा चलाने का एलान किया गया है, जबकि इस कार्रवाई को वहां के मेयर जोहरान ममदानी ने देश के संघीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। अंतरराष्ट्रीय कानून का सर्वोपरि सिद्धांत हर देश की संप्रभुता का सम्मान है, जिसका किसी देश को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी उच्छृंखल देश के खिलाफ भी संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी से बहुपक्षीय बल के जरिए ही वैध कार्रवाई की जा सकती है। मगर इस मामले में संयुक्त राष्ट्र तो दूर, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के सहयोगी देशों की सहमति भी प्राप्त नहीं की। इस तरह वह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए 'एकतरफा कार्रवाई' के अपने चलन को एक नए मुकाम पर ले गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य का ऐसा व्यवहार नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए खुली चुनौती है। इससे दुनिया के हर हिस्से में हमलों की धमकी देने, कमजोर देश को डराने, और मनमाने ढंग से दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है। ट्रंप प्रशासन ने जिस तर्क को आधार बनाकर वेनेजुएला पर कार्रवाई की, आशंका है कि वह वैसी ही दलील ग्रीनलैंड, क्यूबा, मेक्सिको और यहां तक कि आगे चल कर कनाडा के खिलाफ भी गढ़ सकता है। इसीलिए वेनेजुएला पर हमले से अधिकांश देशों के कान खड़े हुए हैं और विश्व समुदाय के बहुत बड़े जनमत ने इसकी निंदा की है।

ब्लॉग

'भजन-राज' यानी 'भरोसे के शासन' में राजस्थान के नये आयाम

ललित गर्ग

राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का हालिया दौरा किसी औपचारिक कार्यक्रम या शिष्टाचार भर तक सीमित नहीं था, वह एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत, एक भरोसे की सार्वजनिक मुहर और एक स्थायित्व का उद्घोष था। जाते-जाते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाकर अमित शाह ने यह जता दिया कि प्रदेश की कमान अब पूरी तरह ऐसे नेतृत्व के हाथों में है, जिस पर केंद्रीय आलाकमान को केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि गहरा संतोष भी है। जिसे कभी राजनीतिक गलियारों में 'सरप्राइज पैकेज' कहकर देखा गया था, वही नेतृत्व आज राजस्थान की स्थिरता, सुशासन और भविष्य की ठोस नींव के रूप में स्थापित हो चुका है और राजस्थान की स्वर्णगाथा लिखने को तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक विशिष्ट और लगातार सफल रहा प्रयोग यह रहा है कि वे सत्ता और संगठन में नए चेहरों को निर्णायक जिम्मेदारियां सौंपने से नहीं हिचकते। पर्दे के पीछे वर्षों तक ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अचानक मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल जैसे पदों पर आसीन करना मोदी की राजनीतिक शैली का साहसिक पक्ष रहा है। इन निर्णयों ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि राजनीति में अनुभव के साथ-साथ चरित्र, प्रतिबद्धता और संगठन के प्रति निष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना भी ऐसा ही एक निर्णय था, जिसने आरंभ में अनेक लोगों को आश्चर्य में डाला। किंतु समय ने सिद्ध कर दिया कि यह निर्णय भावनात्मक नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक समझ और दूरदृष्टि पर आधारित था।

मुख्यमंत्री पद संभालते ही भजनलाल शर्मा ने यह साफ कर दिया कि वे सत्ता को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। उनका एजेंडा कुर्सी बचाने का नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने का है। राजस्थान लंबे समय तक गुटीय राजनीति, शक्ति-संतुलन और पर्दे के पीछे चलने वाले समीकरणों से जूझता रहा है। सत्ता के भीतर ही सत्ता को चुनौती देने वाली प्रवृत्तियां यहां सामान्य रही हैं। भजनलाल शर्मा ने बिना किसी टकराव, बिना शोर-शराबे और बिना किसी को अपमानित किए, इन सभी प्रवृत्तियों को धीरे-धीरे अप्रासंगिक कर दिया। उन्होंने शासन को व्यक्ति-केंद्रित नहीं, बल्कि प्रणाली-केंद्रित बनाया। यही कारण है कि आज निर्णय तेजी से होते हैं, उन पर अमल भी होता है और उनकी जवाबदेही भी तय होती है। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है, जो केवल कागजों या भाषणों तक सीमित नहीं रही। विशेष रूप से पेपर लीक माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई ने सरकार की मंशा और मुख्यमंत्री के साहस को स्पष्ट रूप से उजागर किया। वर्षों से यह माफिया लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उस पर हाथ डालने का साहस कोई नहीं कर पाया। भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया। एसआईटी के गठन, त्वरित जांच, बड़े नामों की गिरफ्तारी और बिना किसी दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया कि यह सरकार केवल घोषणाओं में नहीं, परिणामों में विश्वास रखती है। इससे न केवल युवाओं का भरोसा लौटा, बल्कि यह संदेश भी गया कि अब राजस्थान में कानून से बड़ा कोई नहीं है।

इसी प्रकार, दशकों से प्यास से जूझ रहे राजस्थान के लिए ईआरसीपी परियोजना पर मध्य प्रदेश के साथ हुआ ऐतिहासिक समझौता मुख्यमंत्री की राजनीतिक परिपक्वता और संवाद क्षमता का प्रमाण है। जिस योजना को वर्षों तक केवल चुनावी वादों और फाइलों में उलझाकर रखा गया था, उसे उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग और पड़ोसी राज्य के साथ सकारात्मक संवाद के जरिए वास्तविकता में बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। यह निर्णय बताता है कि भजनलाल शर्मा टकराव की राजनीति के बजाय समाधान की राजनीति में विश्वास रखते हैं। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भी उनकी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई नरमी नहीं है। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपराधियों में कानून का भय-ये सभी कदम इस बात के प्रमाण हैं कि राज्य में सत्ता का इकबाल लौट रहा है। आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है और अपराधी खुद को असुरक्षित। यह सुशासन का सबसे ठोस संकेत होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'विकसित भारत' की संकल्पना को राजस्थान में जमीन पर उतारने में भी मुख्यमंत्री की सक्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचें, यह केवल नारा नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकता बनी है। फैसलों में स्पष्टता, गति और निष्पक्षता-इन तीनों का संतुलन उनकी कार्यशैली को विशिष्ट बनाता है। यही कारण है कि विपक्ष भी आज ठोस आलोचना के बिंदु खोजने में असहज नजर आता है। भजनलाल शर्मा के शासन की चर्चा करते समय उनके चारित्रिक और व्यक्तिगत गुणों का उल्लेख अत्यंत आवश्यक है। राजनीति में जहां दिखावा, आडंबर और अहंकार आम बात हो चली है, वहीं भजनलाल शर्मा अपनी सरलता, सहजता और सादगीपूर्ण जीवनशैली के लिए पहचाने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद भी उनके व्यवहार, भाषा और जीवन-शैली में कोई कृत्रिम बदलाव नहीं आया। वे निर्णय लेते समय दृढ़ होते हैं, लेकिन संवाद में विनम्र रहते हैं। उनका राजनीतिक कौशल शोर में नहीं, बल्कि परिणामों में दिखाई देता है। वे जानते हैं कि कब कठोर होना है और कब संयम रखना है। यही संतुलन उन्हें भीड़ से अलग करता है। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान और जनता के प्रति उत्तरदायित्व-ये सभी गुण उनके नेतृत्व को नैतिक आधार प्रदान करते हैं।

राजस्थान के अब तक के मुख्यमंत्रियों का शासन बहुआयामी अनुभवों से भरा रहा है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक न्याय, विकासात्मक प्राथमिकताओं और राजनीतिक स्थिरता-इन सभी के विविध रूप देखने को मिलते हैं। हीरालाल शास्त्री और जय नारायण व्यास जैसे प्रारंभिक मुख्यमंत्रियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। मोहनलाल सुखाड़िया का दीर्घकालीन शासन सिंचाई, पंचायतीराज और सामाजिक सुधारों के लिए स्मरणीय रहा, जिसे 'आधुनिक राजस्थान' की आधारशिला माना जाता है। बाद के वर्षों में हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत ने कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा-स्वास्थ्य और विकेंद्रीकरण पर बल दिया, जबकि भैरोंसिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के शासन में आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश, सड़क-बिजली और प्रशासनिक सख्ती पर अधिक जोर दिखा। इन सबके तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भजनलाल शर्मा का शासन अपेक्षाकृत नया होते हुए भी "सुशासन, अनुशासन और डिलीवरी" के संकल्प के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। उनका फोकस प्रशासनिक चुस्ती, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, केंद्र-राज्य समन्वय और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर है। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के शासन जहाँ दीर्घ अनुभव और स्थापित नीतिगत पहचान के लिए जाने जाते हैं, वहीं भजनलाल शर्मा का शासन अपेक्षाओं, परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति और नई कार्यशैली के परीक्षण के दौर में है। इस प्रकार राजस्थान की राजनीति में उनका कार्यकाल परंपरा और परिवर्तन-दोनों के बीच एक सेतु की तरह देखा जा सकता है, जहाँ पूर्व शासनों की उपलब्धियों से सीख लेकर भविष्य के लिए अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी शासन मॉडल गढ़ने का प्रयास परिलक्षित होता है।

आज राजस्थान में 'भजन राज' का अर्थ केवल सत्ता का संचालन नहीं, बल्कि भरोसे का शासन है। ऐसा शासन, जहां कार्यकर्ता खुद को गौरवान्वित महसूस करता है और आम नागरिक खुद को सुरक्षित। केंद्रीय आलाकमान की खुली छूट और अमित शाह की पीठ थपथपाहट ने मुख्यमंत्री को और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने का संबल दिया है। यह संकेत साफ है कि भजनलाल शर्मा अब केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक स्थापित, विश्वसनीय और सक्षम नेतृत्व के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं। जो लोग अब भी किसी बड़े बदलाव या सत्ता-समीकरण के इंतजार में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भजनलाल शर्मा का नेतृत्व कोई संयोग नहीं, बल्कि राजस्थान को एक स्थिर, सुशासित और स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाने वाला सुविचारित संकल्प है। वे केंद्रीय नेतृत्व की कसौटी पर 24 कैरेट खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके अब तक के कार्य इस प्रतिबद्धता की ठोस गवाही देते हैं।

मकर संक्रांति सामाजिक समरसता का प्रतीक है- आकांक्षा

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। राष्ट्र सेविका समिति सुलतानपुर विभाग द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का स्थान गभड़यि चौकी के पीछे, गभड़यि वार्ड स्थित प्राथमिक विद्यालय रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सुश्री आकांक्षा उपस्थित रहीं। सुश्री आकांक्षा ने अपने संबोधन में कहा कि मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक पावन पर्व है, जो प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। खिचड़ी भोज की परंपरा आपसी प्रेम, सेवा और समानता की भावना को सुदृढ़ करती है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनते हैं। राष्ट्र सेविका समिति इसी भावना के साथ सेवा, संस्कार और संगठन के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। विशिष्ट उपस्थिति में कुसुम सिंह (विभाग संचालिका), सुमन सिंह (विभाग कार्यवाहिका) तथा डॉ. सीमा सिंह (जिला कार्यवाहिका) उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन रंजना मिश्रा (जिला बौद्धिक प्रमुख) द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र सेविका समिति की सभी दायित्ववान बहनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही नगर की अन्य गणमान्य बहनों की भी सहभागिता उल्लेखनीय रही।

नौंवी कक्षा तक के स्कूल खुले, कोहरे के बीच कांपते हुए पहुंचे छात्र

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ में शुक्रवार से जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा नौंवी तक के स्कूल खोल दिए गए। सुबह के समय शहर में घना कोहरा छाया रहा, इसके बावजूद छात्र-छात्राएं स्कूल जाते हुए नजर आए। वेस्ट एंड रोड समेत कई इलाकों में बच्चे बेहद सावधानी से स्कूल पहुंचते दिखे।

कई दिन बाद खुले स्कूल, ठंड में ठिठुरे बच्चे

कई दिन बाद स्कूल खुलने पर बच्चों को भीषण ठंड और घने कोहरे का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद गुरुवार को सुबह 11 बजे तक भी कोहरा नहीं छंट सका। ठंड के चलते बच्चे कांपते हुए स्कूल पहुंचते नजर आए।

दृश्यता बेहद कम, वाहन रेंगते दिखे

पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी और शीतलहर के चलते मेरठ और आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा। गुरुवार सुबह दृश्यता इतनी कम थी कि 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चलते दिखे। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से सफर करना पड़ा।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

भीषण कोहरा और कड़ाके की ठंड में बच्चों का स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं माना जा रहा है। कम दृश्यता और ठंड को देखते हुए अभिभावकों में किसी बड़े हादसे की आशंका को लेकर चिंता बनी हुई है। कई अभिभावक खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते नजर आए।

सूरज नहीं निकला, ठंड से राहत नहीं

बीते कई दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से ठंड से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एम. शमीम ने बताया कि अगले दो दिन तक कोहरा और सर्दी ऐसे ही बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं।

पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर हुआ गहन मंथन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय स्तर की एक वर्चुअल बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें देशभर से करीब आधा सैकड़ा पदाधिकारियों ने सहभागिता की। बैठक के दौरान पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा पत्रकारों की सुरक्षा रहा। वक्ताओं ने पत्रकारिता के दौरान बढ़ते जोखिम, उत्पीड़न, हमलों तथा प्रशासनिक उपेक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने, जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को संरक्षण देने तथा संगठनात्मक स्तर पर एकजुट होकर आवाज बुलंद करने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस विषय को लेकर भविष्य में केंद्र व राज्य सरकारों से संवाद स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी प्रदेशों के पदाधिकारी अपने-अपने राज्यों में सक्षम और जिम्मेदार लोगों से मिलकर इस दिशा में ठोस प्रयास करें। राष्ट्रीय संयोजक डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव ने स्थानीय पत्रकारों की समस्याओं पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को भी सम्मान मिलना चाहिए और उनकी एक स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए। बिहार राज्य अध्यक्ष अकबर इमाम ने कहा कि बिहार में संगठन मजबूत स्थिति में है और लगातार पत्रकार हितों के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं बिहार राज्य के पदाधिकारी जैकी शर्मा ने कहा कि वे मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर प्रभावी ढंग से आवाज उठाएंगे तथा किसी भी परिस्थिति में पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। अयोध्या मंडल प्रभारी बी.

ताज महल में अगले दो दिन फ्री एंट्री, आज होगी कव्वाली... चढ़ाई जाएगी अब तक की सबसे लंबी चादर

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। सात अजूबों में से एक ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां सालाना उर्स गुरुवार से धार्मिक रस्मों और भारी उत्साह के साथ शुरू हो गया। उर्स के उपलक्ष्य में स्मारक में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया। यानि एंट्री बिल्कुल फ्री। इसके चलते पहले ही दिन करीब 60 हजार पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए एएसआई (ASI), ताज सुरक्षा पुलिस और सीआईएसएफ (CISF) को दिनभर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

सालाना उर्स साल का वह इकलौता समय होता है जब ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों वाले तहखाने को आम जनता के लिए खोला जाता है। गुरुवार को हजारों की संख्या में देशी-विदेशी सैलानियों ने इन असली कब्रों का दीदार किया। निःशुल्क प्रवेश के कारण सुबह से ही स्मारक के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं।

उर्स का कार्यक्रम और रस्में

शाहजहां का यह 371वां उर्स तीन दिनों तक यानी 17 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन (गुरुवार) को 'गुस्ल' की रस्म अदा की गई। इसके बाद एएसआई अधिकारियों और उर्स कमेटी के सदस्यों ने मिलकर फल और फूलों की चादर चढ़ाई। दूसरे दिन (शुक्रवार) को शुक्रवार को 'संदल' की रस्म निभाई जाएगी और शाम को कव्वाली का आयोजन होगा। फिर तीसरे दिन (शनिवार) भव्य 'चादरपोशी' होगी, जिसमें रिकॉर्ड 1,720 मीटर लंबी सतरंगी चादर चढ़ाई जाएगी। इसके बाद लंगर वितरित किया जाएगा।

सुरक्षा के बीच अव्यवस्था और बिछड़े लोग

भारी भीड़ के कारण ताजमहल परिसर में कई जगह अव्यवस्थाएं भी देखने को मिलीं। निःशुल्क प्रवेश का लाभ उठाने आए कई पर्यटकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए मुख्य गुंबद के बाहर ही जूते-चप्पल उतार दिए, जबकि उद्यान क्षेत्र में भी लोगों की अनियंत्रित चहलकदमी देखी गई। भीड़ का आलम यह था कि करीब तीन दर्जन लोग (बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग) अपने परिजनों से बिछड़ गए। हालांकि, ताज सुरक्षा पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बिछड़े हुए लोगों को खोजा और उन्हें उनके परिवारों से मिलवाया।

शुक्रवार के लिए जरूरी जानकारी

आज (शुक्रवार) होने के कारण ताजमहल की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव रहेगा। सुबह से दोपहर 2:00 बजे तकः स्मारक आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। दोपहर 2:00 बजे के बादः प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क (फ्री एंट्री) होगा और लोग असली कब्रों को देख सकेंगे। स्थानीय नमाजीः हर शुक्रवार की तरह नमाजियों के लिए प्रवेश की व्यवस्था पूर्व की तरह ही सामान्य रहेगी। उर्स के अगले दो दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

महिला के शरीर में है भूत, इलाज के नाम पर किया गैंगरेप... कानपुर में बुजुर्ग तांत्रिकों ने की हैवानियत

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। यूपी के कानपुर जिले में तंत्र-मंत्र के नाम पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। 65 और 70 साल के दो तांत्रिकों ने भूत भागने के नाम पर कमरे में बंद कर महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता का मामा उसे तांत्रिक के पास ले गया था। महिला की उम्र 22 साल बताई जा रही है और वह शादीशुदा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जिले के सजेती पुलिस थाना क्षेत्र की है।

थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 22 वर्षीय महिला पिछले करीब दो वर्षों से मानसिक रूप से बीमार चल रही है। उसके पिता ने बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युवती के मामा के कहने पर परिजन उसे तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिकों ने परिजनों को बताया कि युवती पर किसी बुरी आत्म या शैतान का साया है। झाड़-फूंक करने के लिए घाटमपुर के बसौरा निवासी 70 वर्षीय राम जीवन नाम के तांत्रिक उन्हें घर बुलाया, जहां 65 साल का दूसरा तांत्रित पहले से ही मौजूद था।

बंद कमरे में युवती से घंटों गैंगरेप

तांत्रिकों ने कहा कि युवती पर भूत का साया है और उसे अकेले कमरे में ले जाकर भूत भगाना पड़ेगा, जिस पर पिता राजी हो गए। कमरे में युवती को बंद करने के बाद पहले तंत्र-मंत्र का नाटक किया और फिर दोनों बुजुर्ग तांत्रिकों ने कई घंटों तक युवती के साथ बारी-बारी से रेप किया।

जब बेहोश हो गई युवती, तब कमरे से बाहर निकले दोनों तांत्रिक

घंटों गैंगरेप के बाद जब युवती बेहोश हो गई, तब दोनों तांत्रिक कमरे से बाहर निकले और वहां से फरार हो गए। होश आने पर महिला ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। युवती के पिता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से थोड़ी दूर से ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और महिला का मेडिकल टेस्ट कराया गया है।

संजय सिंह के आचार संहिता मामले की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 4 फरवरी को

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। सुल्तानपुर जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से जुड़े एक पुराने मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। यह कार्यवाही प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की है। अधिवक्ता मदन सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी। अदालती कार्यवाही स्थगित होने का मुख्य कारण एमपी-एमएलए जज का अवकाश पर होना था। जज बार काउंसिल चुनाव में ड्यूटी पर थे, जिसके चलते शुक्रवार को कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला बंधुआ कला क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। मुकदमा वर्तमान में साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है। यह घटना 13 अप्रैल 2021 की है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक सभा आयोजित की गई थी। यह सभा जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अन्य आरोपियों ने पहले ही जमानत प्राप्त कर ली थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपए के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया था। जून में विशेष कोर्ट ने इन आरोपियों के अधिवक्ता की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे। अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि इस मामले में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी और वादी मुकदमा के साथी तथा तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर अजय पाल की गवाही भी हुई

नोएडा में बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड, शहर में कब से बिगड़ेगा मौसम?

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों के दौरान नोएडा प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो नोएडा में AQI 344 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जो रेड ज़ोन की श्रेणी में आता है। खराब हवा के कारण बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है।

मौसम विभाग के अनुसार नोएडा और आसपास के इलाकों में अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है। इसे देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत के मुताबिक 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी हवाओं के असर से हल्की बारिश की संभावना है। बारिश होने के बाद ठंड और तेज हो सकती है। अधिकतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

ठंडी हवाओं के चलते लोगों को कंपकंपाती ठंड का सामना करना पड़ सकता है। 15 जनवरी से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के चलते इसका सीधा असर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली होते हुए ठंडी हवाएं नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चलेंगी। उनका यह भी कहना है कि नोएडा में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। शहर में लगातार चल रहे निर्माण कार्य, धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम न होना और वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी से हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। रेड ज़ोन में आने के बावजूद कई इलाकों में निर्माण कार्य जारी है, जिससे हालात और खराब हो रहे हैं। मौसम विभाग और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यदि कोहरा और प्रदूषण इसी तरह बना रहा तो आगे और अलर्ट जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने और मौसम को देखते हुए अपनी दिनचर्या तय करने की सलाह दी गई है।

बढ़ाई गई स्कूल की छुट्टियां

जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर खराब मौसम के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। कल आदेश जारी हुआ था कि 16 तारीख यानी शुक्रवार से सभी स्कूल अपने निर्धारित समय पर खोले जाएंगे। हालांकि, बढ़ती ठंड को देखते हुए एक बार फिर जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अंकुर पवार ने जनपद गौतम बुद्ध नगर में 16 और 17 तारीख तक स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

कानपुर की छतें बनीं पावर हाउस! हो रहा 64 मेगावाट बिजली का उत्पादन

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर शहर की छतें अब बिजली उत्पादन के नए केंद्र बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से कानपुर नगर में सोलर रूफटॉप सिस्टम की क्षमता 64 मेगावाट तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा) के आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक 20,756 सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। इससे कानपुर नगर सोलर रूफटॉप स्थापना के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

विभाग के अनुसार यह योजना न केवल बिजली उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, 64 मेगावाट सौर क्षमता से प्रतिवर्ष लगभग 9.6 करोड़ यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।

मौजूदा बाजार दरों पर इस बिजली का वार्षिक आर्थिक मूल्य 34 से 38 करोड़ रुपये तक अनुमानित है। यदि इतनी बिजली पारंपरिक स्रोतों से खरीदी जाती, तो सरकार, संस्थानों और उपभोक्ताओं पर इतनी बड़ी राशि का बोझ पड़ता।

2024 में शुरू हुआ काम

सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाले घरों और संस्थानों के बिजली बिल में भी काफी कमी आई है। फरवरी 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत जिले में सोलर सिस्टम लगाने की रफ्तार लगातार बनी हुई है। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 80 से 90 नए सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत आवासों के अलावा बहुमंजिला भवनों, हाउसिंग सोसाइटियों के कॉमन एरिया और अन्य स्थानों पर भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है।

कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी

पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो 64 मेगावाट सौर उत्पादन से प्रतिवर्ष करीब 80 हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ रही है। यह कमी पर्यावरण के लिए लगभग 35 लाख पेड़ लगाए जाने के बराबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षमता से प्रतिदिन औसतन 30 से 35 हजार शहरी घरों की बिजली आवश्यकता आसानी से पूरी की जा सकती है। कोयला आधारित बिजली की तुलना में सौर ऊर्जा सस्ती, प्रदूषण-मुक्त और स्थायी समाधान साबित हो रही है। योजना के तहत प्रति किलोवाट सोलर सिस्टम से रोजाना औसतन 5 यूनिट बिजली उत्पादित हो रही है। सिस्टम की लागत प्रति किलोवाट 6065 हजार रुपये है।

कितनी मिलती है सब्सिडी?

केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से 1 किलोवाट पर 45 हजार रुपये तक अनुदान तथा अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक सहायता उपलब्ध है। साथ ही बैंकों से 67 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी दी जा रही है। परियोजना अधिकारी, नेडा, कानपुर नगर राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है और स्थापना की गति निरंतर बढ़ रही है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है और जिले में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कानपुर अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक उभरता हुआ मॉडल शहर बन रहा है, जहां छतें न केवल छाया दे रही हैं, बल्कि बिजली भी उत्पन्न कर रही हैं। यह बदलाव ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भीषण ठंड-कोहरे की मार... नोएडा में 17 जनवरी तक बंद रहेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में भीषण ठंड की वजह से एक बार से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाकर अब 17 जनवरी तक कर दी हैं। 18 जनवरी से स्कूलों के खुलने की उम्मीद है। हालांकि भीषण ठंड के हालात यूं ही बने रहे तो एक बार फिर से छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल यह आदेश 17 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है। इस आदेश के तहत नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को की छुट्टियां की गईं हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 17 जनवरी तक नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि इस आदेश को जारी करने में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने 16-17 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी करने का आदेश 15 जनवरी की शाम को जारी न करके 16 जनवरी की सुबह जारी किया। इस वजह से सुबह भीषण ठंड में भी पैरेंट्स और बच्चे परेशान होते हुए दिखाई दिए।

स्कूलों की ओर से सुबह करीब 8 बजे इस जानकारी को आगे भेजा गया। हालांकि तब तक काफी देर हो गई थी। छात्र-छात्राओं के साथ उनके पैरेंट्स भी स्कूलों के बाहर दिखाई दिए जो बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल पहुंचे हुए थे।

बता दें कि भीषण ठंड का कहर पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री से भी कम दर्ज किया जा रहा है। वहीं शीत लहर का प्रकोप और कोहरे के हालात बने हुए हैं। इसी स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियों का आदेश जारी किया है। स्कूलों की छुट्टियां 18 जनवरी तक घोषित की गई हैं। इसके बाद 19 जनवरी यानी सोमवार को संभवतः स्कूल खोले जाएंगे।

शीत लहर का प्रकोप

15 जनवरी को सुबह के वक्त पूरे एनसीआर में भीषण ठंड और कोहरा देखने को मिला। सुबह करीब 10 बजे तक कई इलाकों में घना कोहरा दिखाई दिया जहां पर विजिबिलिटी 20-30 मीटर ही रह गई थी। सुबह 11 बजे के बाद हालात थोड़े सामान्य हुए। यही हाल 16 जनवरी को भी दिखाई दिया जहां सुबह के वक्त कई इलाकों में घना कोहरा दिखाई दिया।

ये 4 संकेत बताते हैं कि आपका गीजर फटने वाला है! तुरंत चेक करके कराएं ठीक

अगर आपके घर में गीजर लगा है तो उसमें दिखने वाले कुछ संकेतों पर खास नजर रखें। वरना ये फट भी सकता है।

सर्दी का मौसम है, ऐसे में हर किसी के घर में गीजर का इस्तेमाल हो रहा है। इस मौसम में नहाने से लेकर बर्तन धोने तक के लिए लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आए दिन गीजर फटने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। यदि आप नहीं चाहते कि आपके घर का गीजर भी फट जाए तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

दरअसल, हर गीजर में समय-समय पर कुछ संकेत दिखाई देते हैं जो उसके सही कामकाज और सुरक्षा का अंदाजा देते हैं। इन संकेतों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। सही समय पर रखरखाव और सतर्कता आपके घर को सुरक्षित बनाए रखती है और बिजली बिल को भी कम करती है। इस लेख में हम आपको गीजर के प्रमुख संकेत और सुरक्षा उपाय विस्तार से बताएंगे।

1. लीकेज

इस संकेत को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

ध्यान रखें कि गीजर से पानी टपक रहा है, तो ये पाइप की खराबी का संकेत है।

इससे ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए तत्काल लीकेज सही कराएं।

2. असामान्य आवाज

लोगों को लगता है इलेक्ट्रोनिक चीजों के इस्तेमाल के समय आवाज आना स्वाभाविक है।

कड़क-धड़क या बबलिंग जैसी आवाजें हीटिंग एलिमेंट की समस्या बता सकती हैं।

ऐसी आवाजें आने पर तत्काल ही मैकेनिक को बुलाकर इसे चेक कराएं।

3. ब्लिंकिंग या खराब लाइट

गीजर की इंडिकेटर लाइट बार-बार ब्लिंक कर रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फॉल्ट की चेतावनी हो सकती है।

ऐसे समय में मैकेनिक को बुलाकर इसकी वजह जांचें।

अगर लाइट में कुछ खराबी आई है तो तत्काल प्रभाव से उसे ठीक कराएं।

4. जंग दिखने लगे

अगर गीजर में कहीं पर जंग दिख रही है तो संभलना जरूरी है।

जंग की वजह से इसके काम करने में दिक्कत आ सकती है।

तुरंत मैकेनिक को बुलाकर चेक कराएं और यदि जंग वाला हिस्सा बदला जा सके तो उसे बदलवाएं।

ये बात रखें ध्यान

हर 6-12 महीने में गीजर की सर्विस करवाना सुरक्षा के लिए जरूरी है।

ओवरहीटिंग रोकने के लिए थर्मोस्टेट सही रखें और बच्चों को गीजर से दूर रखें।

डायबिटीज का हर चौथा मरीज भारत से, सेहत से लेकर जेब तक सबपर पड़ रहा इस बीमारी का असर

द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के एक चौथाई से ज्यादा डायबिटिक लोग भारत में रहते हैं। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसे डायबिटीज के कारण सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।

भारतीय आबादी में जिन क्रॉनिक बीमारियों के मामले सबसे तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, उनमें डायबिटीज प्रमुख है। हाई ब्लड शुगर वाली ये समस्या यहां जिस गति से लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है, इसे देखते हुए भारत को 'डायबिटीज कैपिटल' कहा जाने लगा है। डायबिटीज सिर्फ खून में ग्लूकोज बढ़ने की समस्या नहीं है। धीरे-धीरे ये स्थिति आपकी आंखों, किडनी, लिवर, पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता सभी को नुकसान पहुंचाने लगती है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में डायबिटीज एक बड़ी महामारी बनती जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक अनुमान के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के 77 मिलियन (7.7 करोड़) लोग टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित हैं।

लगभग 2.5 करोड़ लोग प्रीडायबिटिक हैं जिन्हें भविष्य में डायबिटीज होने का ज्यादा खतरा है।

50% से ज्यादा लोगों को अपनी डायबिटिक स्थिति के बारे में पता नहीं है, जिससे अगर इसका जल्दी पता लगाकर इलाज न किया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

डायबिटीज वाले वयस्कों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा दो से तीन गुना ज्यादा होता है।

डायबिटीज की बीमारी न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा रही है, साथ ही इसके कारण आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा है।

डायबिटीज का आर्थिक बोझ

डायबिटीज पर कौन से देश का कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसके लेकर हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसे डायबिटीज के कारण सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। भारत पर इस बीमारी का बोझ 11.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

अमेरिका को सबसे ज्यादा 16.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च उठाना पड़ता है

वहीं चीन तीसरे नंबर पर है, जिसका खर्च 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

नवंबर 2024 में द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के एक चौथाई से ज्यादा डायबिटिक लोग भारत में रहते हैं।

दुनिया की जीडीपी का 1.7% होता है डायबिटीज पर खर्च

ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस और वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के शोधकर्ताओं ने साल 2020 से 2050 तक 204 देशों में डायबिटीज के आर्थिक असर का हिसाब लगाया। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, परिवार के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक देखभाल को छोड़कर, कुल वैश्विक लागत लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया के सालाना सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 0.2 प्रतिशत है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अनौपचारिक देखभाल को शामिल करने पर यह राशि 152 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है जो दुनिया के सालाना जीडीपी का 1.7 प्रतिशत है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में प्रोफेसर और अध्ययन के लेखक क्लॉस प्रेटनर कहते हैं, भारत और चीन के लिए, डायबिटीज पर होने वाला खर्च मुख्य रूप से इस

रोग से

प्रभावित बड़ी आबादी के कारण है, जबकि अमेरिका में उपचार की लागत के कारण खर्च अधिक हो रहा है।

अध्ययन के सह-लेखक माइकल कुह्न कहते हैं यह इस बात का एक साफ उदाहरण है कि डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों के लिए मेडिकल इलाज सिर्फ ज्यादा इनकम वाले देशों के लिए ही क्यों उपलब्ध है? अल्जाइमर रोग या कैंसर की तुलना में डायबिटीज का आर्थिक असर बहुत ज्यादा है।

डायबिटीज की रोकथाम जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना, नियमित रूप से व्यायाम और फिजिकल एक्टिविटी को लेकर लोगों को जागरूक करना और संतुलित आहार पर ध्यान देना डायबिटीज को रोकने और इसके आर्थिक असर को कम करने का सबसे असरदार तरीका है।

टीम ने कहा कि व्यापक डायबिटीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जरिए इस रोग का जल्दी पता लगाना, साथ ही समय पर इलाज उपलब्ध कराना भी जरूरी है ताकि डायबिटीज के कारण होने वाले खर्च को कम किया जा सके।

कामकाजी महिलाएं जरूर अपनाएं ये 5 फैशन टिप्स, हमेशा लगेंगी खूबसूरत

सही

कामकाजी महिलाओं के लिए सही कपड़े चुनना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऑफिस के माहौल में पेशेवर दिखना और साथ ही आरामदायक महसूस करना जरूरी है। सही कपड़े न केवल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं बल्कि पेशेवर छवि भी मजबूत करते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे फैशन टिप्स साझा करेंगे, जो कामकाजी महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकते हैं और उन्हें हर दिन स्टाइलिश और आत्मविश्वासी बनाए रख सकते हैं।

फिटिंग वाले कपड़े पहनें

कपड़ों की फिटिंग सबसे अहम होती है। ढीले या बहुत कसकर फिट होने वाले कपड़े न पहनें क्योंकि ये आपके लुक को बिगाड़ सकते हैं। सही फिटिंग वाले कपड़े न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएंगे बल्कि पेशेवर छवि भी देंगे। अगर आपके पास सही साइज के कपड़े नहीं हैं तो उन्हें सिलवा लें या फिर सही साइज के कपड़े खरीदें। ध्यान रखें कि आपके कपड़े आपके शरीर के आकार के अनुसार होने चाहिए।

रंगों का चयन सोच-समझकर करें

रंगों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे पेशेवर दिखें और आपके व्यक्तित्व को उभारें। काले, नीले, भूरे जैसे रंग ऑफिस के लिए बेहतरीन होते हैं क्योंकि ये गंभीरता और पेशेवरता का एहसास दिलाते हैं। हालांकि, आप चाहें तो हल्के पेस्टल रंग भी चुन सकती हैं, जो ताजगी और नयापन लाते हैं। इसके अलावा आप अपने कपड़ों में छोटे-छोटे रंगीन एक्सेंट जोड़ सकती हैं, जैसे कि दुपट्टा या बेल्ट, जो आपके लुक को खास बनाएंगे।

कपड़ों की गुणवत्ता पर ध्यान दें

कपड़ों की गुणवत्ता बहुत जरूरी होती है। सस्ते कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं और उनका लुक भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े ही खरीदें। सूती, लिनेन और ऊनी कपड़े सबसे अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं और आरामदायक भी होते हैं। इसके अलावा इनकी देखभाल करना भी आसान होता है। अच्छे कपड़ों का चुनाव आपके पेशेवर लुक को निखारता है और आपको आत्मविश्वासी बनाता है।

एक्सेसरीज का सही उपयोग करें

एक्सेसरीज आपके लुक को पूरा करती हैं इसलिए इन्हें नजरअंदाज न करें। हालांकि, एक्सेसरीज चुनते समय संतुलन बनाए रखें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे। छोटे कान की बालियां, एक साधारण घड़ी और एक अच्छी गुणवत्ता वाला हैंडबैग आपके लुक को खास बनाएंगे। इसके अलावा आप हल्के गहनों का भी चयन कर सकती हैं, जो आपके व्यक्तित्व को उभारेंगे और आपको आत्मविश्वासी बनाए रखेंगे। सही एक्सेसरीज आपके पेशेवर लुक को निखारती हैं।

फुटवियर्स का चयन सोच-समझकर करें

फुटवियर्स का चयन करते समय आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी होना चाहिए। हाई हील्स फुटवियर्स पहनना चाहती हैं तो मध्यम ऊंचाई वाले चुनें जो पूरे दिन पहनने योग्य हों। फ्लैट फुटवियर्स भी अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि ये आरामदायक होते हैं और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा आरामदायक सैंडल्स भी पहन सकती हैं, जो आरामदायक और स्टाइलिश दोनों होते हैं। सही फुटवियर्स का चयन आपके पूरे लुक को संतुलित करता है।

कम सैलरी के कारण अगर आपका भी पीएफ नहीं कटता तो आपके लिए है ये गुड न्यूज

नौकरीपेशा लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आपकी सैलरी 15 हजार रुपये से थोड़ी अधिक होने के कारण आप ईपीएफ (श्वक्कस्न) के दायरे से बाहर रह गए हैं, तो अब उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्वक्कस्नह्र) को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ईपीएफ की वेतन सीमा (वेज सीलिंग) बढ़ाने को लेकर चार महीने के भीतर अंतिम फैसला लिया जाए।

यह आदेश उस सीमा को लेकर है जो पिछले 11 वर्षों से जस की तस बनी हुई है। कोर्ट ने माना कि लंबे समय से सीमा में बदलाव न होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी ईपीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना से वंचित हो रहे हैं।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने साफ कहा कि अब यह तय किया जाना जरूरी है कि वेतन सीमा बढ़ाई जाए या नहीं। कोर्ट ने केंद्र और श्वक्कस्नह्र से इस मुद्दे पर समयबद्ध निर्णय लेने को कहा है।

11 साल से क्यों अटकी है वेतन सीमा?

फिलहाल ईपीएफ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह तय है। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (ष्ठ्र) मिलाकर यह राशि 15 हजार रुपये तक है, उनके लिए पीएफ कटौती अनिवार्य होती है। यह सीमा सितंबर 2014 में तय की गई थी और तब से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।

इस दौरान महंगाई, न्यूनतम वेतन और आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन ईपीएफ की वेतन सीमा वहीं की वहीं बनी हुई है। नतीजतन, मामूली वेतन वृद्धि होते ही लाखों कर्मचारी ईपीएफ के दायरे से बाहर हो जाते हैं।

सोशल सिक्योरिटी से वंचित हो रहे कर्मचारी

याचिका में कहा गया कि मौजूदा नियमों की वजह से बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग ईपीएफ जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना से बाहर हो गए हैं। ईपीएफ का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है, लेकिन पुरानी वेतन सीमा इस मकसद को कमजोर कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी और वेतन सीमा बढ़ने से ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ का लाभ मिल सकेगा।

अगर 30 हजार हुई सैलरी तो कितनी मिलेगी पेंशन, ये है पूरा कैलकुलेशन

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अगर सरकार पीएफ वेज लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करती है, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन दोगुनी हो जाएगी। नई गणना के मुताबिक, अभी मिलने वाली अधिकतम 7,500 रुपये की पेंशन बढ़कर सीधे 15,000 रुपये महीना हो सकती है।

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर कर्मचारी के मन में रिटायरमेंट को लेकर एक ही सवाल होता है क्या बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन का सहारा काफी होगा? मौजूदा समय में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए ईपीएफओ (EPFO) की मौजूदा पेंशन राशि काफी कम लगती है। लेकिन, अब देशभर के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को वेज लिमिट (Wage Limit) बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है।

क्यों कम रह जाती है आपकी पेंशन?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अभी आपके हाथ में कम पेंशन क्यों आती है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, अभी पेंशन के लिए वेतन की सीमा यानी वेज लिमिट 15,000 रुपये तय है। इसका मतलब यह है कि आपकी बेसिक सैलरी चाहे 50 हजार हो या 1 लाख रुपये, पेंशन की गणना के लिए इसे केवल 15,000 रुपये ही माना जाता है।

जब आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में पैसा जमा करती है, तो उसका एक हिस्सा ईपीएस (EPS) यानी एंप्लॉयी पेंशन स्कीम में जाता है। 15,000 रुपये की सीमा फिक्स होने के कारण ईपीएस में जाने वाला योगदान भी सीमित हो जाता है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की रकम उम्मीद से काफी कम रह जाती है। फिलहाल, इस नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 7,500 रुपये और न्यूनतम 1,000 रुपये की मासिक पेंशन ही मिल पाती है।

बदल जाएगा पेंशन का पूरा गणित

अब बात करते हैं उस बदलाव की, जिसका सबको इंतजार है। चर्चा है कि वेज लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो पेंशन की गणना का पूरा गणित ही बदल जाएगा। पेंशन कैलकुलेट करने का एक सीधा फार्मूला होता है: (पेंशन योग्य सैलरी × नौकरी के साल) / 70।

अभी हम 15,000 रुपये पर गणना करते हैं, तो अधिकतम 35 साल की नौकरी पर पेंशन 7,500 रुपये बनती है। लेकिन, जैसे ही यह बेस 30,000 रुपये होगा, यह आंकड़ा सीधे दोगुना हो जाएगा। इस फार्मूले में 'पेंशन योग्य सैलरी' पिछले 60 महीनों की औसत बेसिक सैलरी होती है। लिमिट बढ़ने का सीधा असर यह होगा कि आपके ईपीएस खाते में हर महीने जमा होने वाली रकम बढ़ जाएगी, जो आपकी मंथली पेंशन को बढ़ा देगी।

सीधे दोगुनी हो सकती है मंथली पेंशन

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो लंबे समय से प्राइवेट नौकरी में हैं। वेज लिमिट 30,000 रुपये होने की स्थिति में, अगर कोई कर्मचारी अधिकतम 35 साल की सर्विस पूरी करता है, तो उसे मिलने वाली अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़कर सीधे 15,000 रुपये हो जाएगी। सिर्फ अधिकतम ही नहीं, बल्कि न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, यह लिमिट बढ़ने पर कर्मचारियों को कम से कम 4,285 रुपये की पेंशन मिल सकती है, जो अभी महज 1,000 रुपये है।

तीखे सवाल पर भड़की ट्रंप की प्रेस सचिव, पत्रकार को बता दिया 'वामपंथी'

वॉशिंगटन, एजेंसी। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिली। गुरुवार, 15 जनवरी को हुई ब्रीफिंग में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट और द हिल के एसोसिएट एडिटर नायल स्टैनज के बीच माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया, जब स्टैनेज ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) से जुड़े मुद्दों पर लगातार कड़े सवाल दागे। सवालों से असहज दिखीं लेविट ने पत्रकार के रुख पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें (वामपंथी कार्यकर्ता) लेफ्ट-विंग एक्टिविस्ट तक कह डाला।

नायल स्टैनेज और लेविट के बीच क्यों बहस हुई?

व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में काफी तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई, जब पत्रकार नायल स्टैनेज ने आईसीई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले साल ICE की हिरासत में 32 लोगों की मौत हुई, यह संख्या एजेंसी के लिए पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एक एजेंट ने रिनी गुड को गोली मारी और उनकी मौत हो गई, और कई अमेरिकी नागरिकों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया।

स्टैनेज ने पूछा कि ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि ICE सबकुछ सही ढंग से कर रहा है। लेविट ने उन्हें रोकते हुए कहा कि रिनी गुड दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से क्यों मारी गई? जब स्टैनेज ने जवाब में कहा कि ICE एजेंट ने बेपरवाह व्यवहार किया, तो लेविट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्टैनेज को पक्षपाती रिपोर्टर, वामपंथी कार्यकर्ता कहा और आरोप लगाया कि वह तथ्यों के बजाय अपनी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। लेविट ने कहा कि हां, क्योंकि आप वामपंथी हैं। आप रिपोर्टर ही नहीं हैं। आपको यहां बैठना भी नहीं चाहिए।

ब्रीफिंग के बाद लेविट ने फिर सवाल किया कि क्या स्टैनेज के पास गैरकानूनी अप्रवासियों द्वारा मारे गए अमेरिकी नागरिकों की संख्या के बारे में जानकारी है, और तर्क दिया कि आईसीई उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका में अवैध रूप से हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आपके पास वे आंकड़े नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आपने उन कहानियों को तक पढ़ा नहीं है। लेविट ने पत्रकारों पर आरोप लगाया कि मीडिया में ऐसे लोग हैं जिनकी दृष्टि पक्षपाती और विकृत है, और जो खुद को ईमानदार पत्रकार का ढोंग कर रहे हैं।

भूकंप के झटकों से दहला अमेरिका का ओरेगॉन, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6 .2 रही

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के ओरेगॉन इलाके के तटीय क्षेत्र में गुरुवार को भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप के इन झटकों की तीव्रता 6.2 रही। हालांकि इसमें अभी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था। नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर द्वारा अभी तक सुनामी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

ओरेगॉन के इस इलाके में अक्सर आते हैं भूकंप

ओरेगॉन के जिस इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वह ओरेगॉन और कैलिफोर्निया की सीमा पर स्थित है और यहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस इलाके में आने वाले अधिकतर भूकंप जमीन के भीतर होते हैं और अक्सर धरती पर महसूस नहीं होते। ओरेगॉन के जिस इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वह ओरेगॉन और कैलिफोर्निया की सीमा पर स्थित है और यहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस इलाके में आने वाले अधिकतर भूकंप जमीन के भीतर होते हैं और अक्सर धरती पर महसूस नहीं होते।

कास्केडिया जोन में आता है ये इलाका

इससे पहले बीते साल सितंबर में भी ओरेगॉन में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यह इलाका कास्केडिया जोन का हिस्सा है।

कास्केडिया जोन उत्तरी वैंकूवर द्वीप से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली भूकंप क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

साल 1700 में यहां 9.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिससे भयंकर सुनामी आई थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर फिर इतनी तीव्रता का भूकंप आया और सुनामी आई तो तटीय इलाकों में भारी तबाही मच सकती है।

पश्चिम एशिया में तनाव : हालात पर भारत की पैनी नजर, ईरान-इस्राइल जैसे देशों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी

तेल अवीव, एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और जोखिमों को देखते हुए भारत ने ईरान के बाद अब इस्राइल में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस्राइल में बढ़ते तनाव और ईरान में प्रदर्शन के बीच भारत ने नागरिकों से सतर्क रहने, सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। सरकार ने इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि इस्राइल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इस्राइली अधिकारियों तथा होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी किए गए सुरक्षा दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है।

विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में इमरजेंसी की स्थिति में भारत के एंबेसी की 24x7 हेल्पलाइन से संपर्क करने का नंबर भी दिया गया है। यह चेतावनी तब जारी की गई है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। इस्राइल और ईरान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।

ईरान में प्रदर्शन और अमेरिका का रुख

बता दें कि ईरान में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका ने देश में सैन्य कार्रवाई के विकल्प को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उनके क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे वैध निशाने होंगे। इस तनाव के बीच तेल अवीव और इस्राइल के दक्षिणी व मध्य इलाकों में कई जगह सार्वजनिक शरण स्थलों को खोलने के आदेश दिए गए हैं।

ईरान से नागरिकों को निकालने की तैयारी में भारत

एक तरफ जहां इस्राइल को लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं दूसरी ओर भारत ईरान में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी भी कर रहा है। बुधवार को भारत के तेहरान स्थित एंबेसी ने भी एक नई एडवाइजरी जारी की। इसमें छात्रों,तीर्थयात्रियों, व्यवसायियों और पर्यटकों सहित इरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध परिवहन साधनों जैसे कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल कर देश छोड़ने की चेतावनी दी गई।

भारतीय नागरिकों को दी गई ये चेतावनी

एंबेसी ने कहा कि भारतीय नागरिकों को प्रदर्शन और विरोध स्थलों से दूर रहना चाहिए और स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखनी चाहिए। साथ ही सभी नागरिकों से कहा गया है कि वे एंबेसी के संपर्क में रहें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। वर्तमान अनुमान के अनुसार, इरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें अधिकांश छात्र हैं।

इस बार निशाना नहीं चूकेगा, ट्रंप पर हमले की तस्वीर शेयर कर ईरान ने दी धमकी

तेहरान, एजेंसी। ईरान के ताजा हालात चिंताजनक हैं। अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच अब ईरान ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली हैं। ईरान ने एक तस्वीर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है।

इस बीच तनावपूर्ण हालात में ब्रिटेन ने तेहरान में अपने दूतावास को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अपने सभी डिप्लोमैटिक स्टाफ को वापस बुला लिया है। ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस ने कहा, हमने तेहरान में ब्रिटिश दूतावास को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। यह अब रिमोटली ऑपरेट होगा। ईरान ने 2024 में पेन्सिलवेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें उन्हें एक कैंपेन रैली में मारने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था।

साथ ही चेतावनी दी गई, इस बार निशाना चूकेगा नहीं।

फारसी से ट्रांसलेट किए गए इस मैसेज की तस्वीरें कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए तेजी से ऑनलाइन फैलीं और ईरान के सरकारी टेलीविजन पर भी दिखाई गईं। यह ब्रॉडकास्ट ट्रंप की बार-बार दी गई चेतावनियों के बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा, अगर ईरान शांति से विरोध करने वालों को मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया ने जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया, वह जुलाई 2024 में पेन्सिलवेनिया के बटलर में एक कैंपेन रैली के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की थी। उस समय थॉमस क्रुक्स नाम के एक बंदूकधारी ने स्टेज पर गोलियां चलाई थीं, जो ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी। इस घटना ने अमेरिका को चौंका दिया था।

हाल के दिनों में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्ते और खराब हो गए हैं। अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद ईरान ने फिलहाल अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है। बढ़ते तनाव के बावजूद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और पिछले दो दशकों से उसने यही रुख बनाए रखा है। कूटनीति युद्ध से कहीं बेहतर है। अराघची ने वाशिंगटन से सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत से समाधान निकालने का आग्रह किया है।

बेअदबमी विवाद पर पंजाब पुलिस का दिल्ली विधानसभा में रिप्लाई, स्पीकर बोले–आतिशी को देना होगा 19 तक जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को हाल ही में खत्म हुए शीतकालीन सत्र में सिख गुरुओं के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' के बारे में अपना लिखित बयान देने का निर्देश दिया है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आतिशी जी को जो नोटिस दिया गया है, वह एक अलग मामला है, क्योंकि यह विषय सदन के पटल पर आते ही प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया था। उन्होंने कहा जो भी कार्रवाई की जा रही है, वह विपक्ष की मांग पर की गई है। विपक्ष के सदस्यों ने खुद मेरे चैंबर में आकर यह मांग रखी थी।

उन्होंने कहा कि 8 तारीख को हमने इस मामले को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। इसके अगले ही दिन यह खबर आती है कि पंजाब सरकार ने जांच भी पूरी कर ली और एफआईआर भी दर्ज कर दी। उन्होंने कहा इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो सदन की प्रक्रिया को चुनौती दी जा रही हो।

स्पीकर ने कहा कि सच को झुठलाया नहीं जा सकता। सदन के प्रति न्याय करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। डीजीपी ने जवाब देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की है। उन्हें अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 22 जनवरी तक का समय दिया गया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा उन्हें भेजे गए एक कम्युनिकेशन में कहा गया है कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन ने आतिशी से 19 जनवरी तक अपना लिखित बयान देने को कहा है। पिछले साल 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली सरकार के कार्यक्रम पर 6 जनवरी को विधानसभा सत्र में चर्चा के बाद आतिशी का सिख गुरुओं के प्रति दिखाए गए अनादर का मुद्दा एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है, इसमें दिल्ली में बीजेपी और AAP शासित पंजाब शामिल हैं।

स्पीकर ने कही थी बैठक में शामिल होने की बात

आतिशी को भेजे गए विधानसभा के कम्युनिकेशन में कहा गया है कि 6 जनवरी को शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान, उन्होंने स्पीकर की बात न मानते हुए दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। जबकि स्पीकर ने उन्हें बताया था कि बहस अगले दिन के लिए लिस्टेड है।

इसमें कहा गया है कि ऐसा करते समय आपने कथित तौर पर सिख गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हुई। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्पीकर ने आपसे बैठक में शामिल होने और सही स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया।

'विपक्ष के क्षेत्रों में हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब', संजय राउत ने चुनाव पर उठाए सवाल

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव के नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। अभी तक के रुझानों में भाजपा बीएमसी समेत अधिकतर नगर निगमों में आगे चल रही है। इन रुझानों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। लंबे समय से बीएमसी की सत्ता पर काबिज शिवसेना यूबीटी इस बार पिछड़ती नजर आ रही है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं।

संजय राउत का आरोप- मतदाता सूची से गायब हुए कई नाम

संजय राउत ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुंबई जैसे शहर में जिस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा, वो बेहद चौंकाने वाला है। शिवसेना यूबीटी, मनसे और कांग्रेस के क्षेत्रों में हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची में गायब मिले, जबकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट किया था।

ईवीएम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। चुनाव आयोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और चुनाव आयोग के स्टाफ के बीच बैठक हुई, जबकि अभी भी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है।' राउत ने आरोप लगाया कि वोटिंग प्रतिशत आने से पहले ही एग्जिट पोल्स के नतीजे आने शुरू हो गए थे। भाजपा ने अपनी जीत की खुशी भी मनानी शुरू कर दी थी।

भाजपा का दावा- बीएमसी में 90 से कम सीटें नहीं जीतेंगे

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने शुरुआती रुझानों को लेकर कहा कि लोग देख रहे हैं कि हमने क्या किया है। हम सिर्फ चुनावी भाषण पर निर्भर नहीं करते।

लोग हमारे पुराने काम देखकर ही हम पर विश्वास कर रहे हैं। हमने लोगों से पूछा है कि अगर शिवसेना यूबीटी काम करना चाहती है तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया? हमने कोरोना महामारी के दौरान भी काफी काम किया था।

उन्होंने कहा कि अगर ठाकरे भाई भी साथ आए हैं या कांग्रेस और एनसीपी हाथ मिला लें, ये लोगों के हित में नहीं है। लोग समझते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ आ रहे हैं। मुंबई में भाजपा 90 सीटें जीतेगी और शिवसेना करीब 40 सीटें। ये नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे। पुणे में हम 115 सीटों से कम नहीं लाएंगे।

बीएमसी चुनाव परिणाम: भाजपा ने निकाय चुनाव के जनादेश पर खुशी जताई, शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने से की तुलना

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत 20 नगर निकायों में चुनाव संपन्न कराए जाने के बाद आज जनादेश आया। भाजपा नेताओं के मुताबिक ये ऐतिहासिक चुनाव परिणाम हैं। पार्टी की उल्लेखनीय सफलता पर भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पहले बिहार में हमें सफलता मिली। त्रिवेदी ने कहा कि इसके बाद केरल में भी भाजपा को कामयाबी मिली। अब महाराष्ट्र के नगर निगम में ये अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से भविष्य के लिए शुभ संकेत है। नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को राज्य की जनता के करारा जवाब दिया है। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं जय-जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें जो समर्थन दिया है, इसके लिए विनम्रता से आभार... ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है... जैसे शिवाजी की चतुरंगिणी सेना मन में उमंग धारण करके चलती थी, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है। भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन के शनदार प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता बहुत समझदार है। पहाड़ से सागर तक, भारत का कोई भी हिस्सा हो, जनता हर जगह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए। आईना साफ करने से मुंह पर लगे कालिख के निशान मिट नहीं सकते। चुघ ने आगे कहा कि आप हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके काले कारनामों पर देश और महाराष्ट्र की जनता वोट की चोट से सजा दे रही है। ये बहुत बड़ी विजय है। ये विजय यात्रा 26 मई, 2014 से चल रही है। आज 11 साल आठ महीने हो गए।

मलाइका अरोड़ा डेटिंग की खबरों पर बोलीं- लोगों को बातें करना पसंद, इससे कोई फायदा नहीं

बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं। अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद उनकी जिंदगी में कौन आया, कौन गया? ऐसे चर्चे सोशल मीडिया पर आम बात हैं। खुद अभिनेत्री का मानना है कि उन्हें किसी भी अनजान शख्स के साथ देखकर लोग उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। हालिया बातचीत में मलाइका ने लंबे समय से चल रही डेटिंग की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है।

हाल ही में, मलाइका ने नम्रता जकारिया शो में शिरकत की और रहस्यमयी व्यक्ति के साथ अपने नए रिश्ते की खबरों को संबोधित किया। अभिनेत्री ने कहा, लोगों को बातें करना पसंद है। अगर आपको किसी के साथ देखा जाता है, आप बाहर जाते हैं और यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। मैं बेवजह की बातों को हवा नहीं देना चाहती, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के चर्चे होना आम बात हो चुकी है।

मलाइका ने कहा, जब भी मैं बाहर निकली हूं, चाहे वो कोई पुराना दोस्त हो, समलैंगिक दोस्त हो, शादीशुदा दोस्त हो, मैनेजर हो या कोई भी हो, मुझे तुरंत उसके साथ जोड़ दिया जाता है। ये सब तो हंसी का पात्र बन गया है। कुछ दिन पहले एक कॉन्सर्ट में मलाइका को रहस्यमयी व्यक्ति संग देखकर उनके नए रिश्ते की खबरों ने जोर पकड़ा था। सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि वो शख्स हीरा व्यापारी हर्ष मेहता है।

प्यार में धोखे मिलने के बाद रिश्तों को लेकर क्या सोचती हैं रश्मि देसाई?

टीवी सीरियल उतरन में तपस्या ठाकुर बनकर फेमस होने वाली रश्मि देसाई अपने नए चैट शो रश्मि दिल से दिल तक को लेकर छाई हुई हैं। अभिनेत्री का शो टीवी स्टार्स के निजी जीवन के बारे में दर्शकों को गहराई से बताएगा, लेकिन असल जिंदगी में खुद इतने सारे धोखे खाने के बाद प्यार और शादी के बारे में रश्मि की राय काफी अलग है। अभिनेत्री का कहना है कि अगर वो किसी के साथ इमोशनली इंवॉल्व होती हैं, तो अपना सब कुछ दे सकती हैं। एक्टर नंदीश संधू से टूटी शादी और कई लड़कों को डेट करने के बाद भी रश्मि देसाई आज भी सही पार्टनर की तलाश में हैं। उन्होंने शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के रिश्ते को लेकर कहा कि दोनों हमेशा मुस्कुराते रहते हैं लेकिन उन दोनों ने जिंदगी में काफी कुछ झेला है। दोनों ने हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया है और यही वजह है कि वे परफेक्ट कपल हैं, जो इमोशनली और प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ हैं।

कपल के बीचे के इमोशंस पर बात करते हुए रश्मि देसाई ने कहा कि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं और मुझे क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं किसी के साथ इमोशनल पार्ट पर जुड़ी तो उसे अपना दिल, जायदाद, घर और पैसा सब कुछ दे दूंगी क्योंकि मेरे लिए इंसान मैटर करता है, लेकिन अब इतने धोखे खाने के बाद मैंने किसी को अपनी तरफ आने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन कहते हैं कि भगवान कोई न कोई रास्ता दिखा ही देता है। इस शो के दौरान मैंने समझा है कि रिश्ता दो लोगों के बीच का होता है, सबका नहीं होता है।

रश्मि देसाई ने कहा कि उन्होंने ये भी सीखा कि काम और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए। अब मैंने अपने इमोशन को काम में शिफ्ट कर दिया है और मुझे काम करना बहुत पसंद है और ये मुझे हील करने का काम करता है और मेरा हैप्पी प्लेस है। उतरन में काम करने के दौरान ही रश्मि की मुलाकात एक्टर नंदीश संधू से हुई थी। कुछ साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों की शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद उनका नाम अरहान खान और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने रिश्ते पर रश्मि ने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन दोनों के मतभेद जगजाहिर थे।

विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी प्रतिष्ठित फिल्म गांधी वार्ता 30 जनवरी को रिलीज होगी

ज़ी स्टूडियोज़ ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी और अपरंपरागत फिल्म गांधी टॉक्स की रिलीज़ तिथि की घोषणा कर दी है, जो 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। आधुनिक भारतीय सिनेमा की यह दुर्लभ मूक फिल्म एक साहसिक रचनात्मक छलांग है, जहाँ मौन कहानी कहने का सबसे सशक्त माध्यम बन जाता है। ऐसे समय में जब सिनेमा को अक्सर भव्यता और ध्वनि से परिभाषित किया जाता है, गांधी टॉक्स अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए संयम, भावना और स्थिरता का चुनाव करती है।

यह फिल्म विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव जैसे असाधारण कलाकारों को एक साथ लाती है, जिन्होंने जानबूझकर कहानी कहने के एक ऐसे रूप को अपनाया है जो पूरी तरह से प्रदर्शन और अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। विजय सेतुपति और अरविंद स्वामी जैसे अभिनेताओं के लिए, एक मूक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का निर्णय शिल्प-आधारित सिनेमा में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव संवाद के बिना भेद्यता और भावनाओं को अपनाते हुए, सूक्ष्म, अभिव्यक्ति-प्रधान प्रदर्शनों के साथ कथा को और समृद्ध करते हैं.

एआर रहमान का संगीत गांधी टॉक्स की भावनात्मक आवाज़ बन जाता है, जो कथावाचक की भूमिका निभाते हुए दर्शकों को फिल्म के भावपूर्ण परिदृश्य से रूबरू कराता है। उनका संगीत मौन को एक शक्तिशाली, गहन अनुभव में बदल देता है, जिससे फिल्म वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित होने योग्य बन जाती है। निर्देशक किशोर बेलेकर ने कहा, गांधी टॉक्स मौन पर भरोसा करने वाली फिल्म है। भारतीय सिनेमा कहानी कहने के एक सदी से अधिक का सफर तय कर रहा है, ऐसे में हम इस माध्यम के सबसे मौलिक रूप - शुद्ध प्रदर्शन और भावना - की ओर लौटना चाहते थे।

गांधी वार्ता एक ऐसी हास्य फिल्म है जो महात्मा गांधी के विचारों और आज के समाज की वास्तविकताओं के बीच के अंतर को दर्शाती है। कहानी एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है जो पैसों की तंगी से जूझ रहा है और कैसे उसका जीवन एक चोर के जीवन से जुड़ जाता है। फिल्म में मूल्यों, लालच और समाज जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

गांधी टॉक्स के साथ, ज़ी स्टूडियोज़ उन उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित फिल्मों को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है जो सिनेमाई मानदंडों को चुनौती देती हैं और भारतीय सिनेमा की भाषा का विस्तार करती हैं। 30 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने वाली गांधी टॉक्स एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देती है।

संदीप वांगा ने दिल दिया का बोल्ड फर्स्ट लुक जारी किया

स्पिरिट के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने के. क्रांति माधव की फिल्म दिल दिया - अ नेकेड ट्रुथ का टाइटल और फर्स्ट-लुक पोस्टर लॉन्च किया,

दिल दिया – अ नेकेड ट्रुथ फिल्म के टाइटल और फर्स्ट-लुक पोस्टर के रिलीज के साथ ही यह फिल्म सुर्खियों में आ गई है। यह आगामी फिल्म के लिए पहला सार्वजनिक कदम है। स्पिरिट के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर ने फिल्म जगत में शुरुआती दिलचस्पी जगा दी है और फिल्म के रिलीज के लिए मंच तैयार कर दिया है। श्रीयस चित्रा – पूर्णा नायडू प्रोडक्शन बैनर के तहत पूर्णा नायडू द्वारा निर्मित और के. क्रांति माधव द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म भावनात्मक संघर्ष और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित एक समकालीन ड्रामा है। के. क्रांति माधव की फिल्म दिल दिया - अ नेकेड ट्रुथ उनकी उस शैली को आगे बढ़ाती है जो भावनात्मक संवेदनशीलता और संयमित कथा शैली से परिपूर्ण है। वर्षों से, उन्होंने सतही नाटक के बजाय मानवीय कमजोरियों को गहराई से छूने वाली कहानियों के लिए ख्याति अर्जित की है। ओनामालु, मल्ली मल्ली इदि रानी रोजू और वर्ल्ड फेमस लवर जैसी फिल्मों में प्रेम, नैतिक दुविधाओं, भावनात्मक टूटन और आंतरिक संघर्ष में उनकी रुचि झलकती है। दिल दिया - अ नेकेड ट्रुथ के साथ, वे इसी तरह के भावनात्मक क्षेत्र में लौटते हैं, इस बार जुनून, असफलता, अंतरंगता और आत्मसम्मान से प्रेरित एक अधिक प्रत्यक्ष और समकालीन दृष्टिकोण से।

फिल्म में चैतन्य राव मदादी, इरा, सखी और जेस्सी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि मणि चंदना, प्रमोदिनी और वीरा शंकर ने सहायक भूमिकाओं में उनका साथ दिया है। कलाकारों का चयन फिल्म के यथार्थवादी कथानक को दर्शाता है, जिसमें स्वाभाविक और जीवंत अभिनय को प्राथमिकता दी गई है। नाटकीयता पर ज़ोर देने के बजाय, कहानी कहने का तरीका पात्रों के आपसी संवाद और परिणामों के माध्यम से भावनाओं को स्वाभाविक रूप से उभरने देता है।

फिल्म का पहला पोस्टर संयमित लेकिन प्रभावशाली ढंग से फिल्म की भावनात्मक दुनिया की झलक पेश करता है। सरल डिजाइन और दिखावे से मुक्त यह पोस्टर संवेदनशीलता, विरोधाभास और आंतरिक उथल-पुथल का संकेत देता है। पोस्टर फिल्म के मुख्य विषयों को स्पष्ट रूप से बताने के बजाय, व्यक्तिगत सच्चाई से प्रेरित एक अंतर्मुखी कहानी का सुझाव देता है। यह दृश्य शैली क्रांति माधव की फिल्म निर्माण शैली से पूरी तरह मेल खाती है, जहां भावनात्मक स्पष्टता और ईमानदारी को दिखावटी तमाशे से अधिक महत्व दिया जाता है।

पूर्णा नायडू द्वारा निर्मित और श्रीकांत वी के सह-निर्माता के रूप में, दिल दिया - अ नेकेड ट्रुथ को एक मजबूत और अनुभवी तकनीकी टीम का समर्थन प्राप्त है। पीजी विंदा ने छायांकन किया है, जिससे एक अंतरंग लेकिन सिनेमाई दृश्य अनुभव प्राप्त होने की उम्मीद है। संगीत फानी कल्याण ने तैयार किया है, जबकि संपादन रा-शा (रवि - शशांक) ने किया है। चिन्ना ने प्रोडक्शन डिज़ाइन का निरीक्षण किया है, धानी ऐले ने प्रचार डिज़ाइन संभाला है, स्टार सर्कल ने डिजिटल मार्केटिंग का प्रबंधन किया है, और प्रचार का नेतृत्व एसके नायडू और फानी कंडुकुरी (बियॉन्ड मीडिया) ने किया है।

भावनात्मक गहराई से सजी एक युवा प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत, दिल दिया - अ नेकेड ट्रुथ आधुनिक रिश्तों का एक ईमानदार और बेबाक चित्रण पेश करने का लक्ष्य रखती है। आदर्शवादी रोमांस से परे जाकर, यह फिल्म भावनात्मक जटिलता और व्यक्तिगत परिणामों से सीधे तौर पर जुड़ती है, और समकालीन तेलुगु सिनेमा में अंतरंगता की नई परिभाषा तलाशने का प्रयास करती है। निर्देशक के स्पष्ट दृष्टिकोण, मजबूत रचनात्मक समर्थन और शीर्षक एवं फर्स्ट-लुक के अनावरण के बाद मिली शुरुआती गति के साथ, दिल दिया - ए नेकेड ट्रुथ को एक नए बॉक्स-ऑफिस पैटर्न के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा।
RNI No: UPHIN/2014/57034
Website : aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय
सम्पर्क: 9839909595, 8765295384
Email: aryavartkrantidainik@gmail.com